नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 246
दि. 09.06.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

2029 की जंग की तैयारी शुरु, इंडिया ब्लॉक ने बनाई साझा रणनीति और दिखाया शक्ति प्रदर्शन

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार विपक्षी दलों का व्यापक राजनीतिक जमावड़ा राजधानी दिल्ली में देखने को मिला, जहां इंडिया ब्लॉक के घटक दलों ने न केवल अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया बल्कि आगामी राजनीतिक लड़ाई की दिशा और रणनीति का भी संकेत दे दिया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक को विपक्ष के लिए केवल एक नियमित राजनीतिक बैठक नहीं, बल्कि वर्ष 2029 के लोकसभा चुनावों की तैयारी के प्रारंभिक खाके के रूप में देखा जा रहा है। लगभग चार घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ साझा मुद्दों पर आक्रामक अभियान चलाने, संसद के भीतर और बाहर समन्वित रणनीति अपनाने तथा गठबंधन को अधिक संगठित और सक्रिय बनाने पर सहमति जताई।

बैठक में देश के विभिन्न हिस्सों से आए विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, वाम दलों और कई क्षेत्रीय संगठनों की मौजूदगी ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि विपक्ष अभी भी भाजपा के खिलाफ एक साझा राजनीतिक मंच को जीवित रखना चाहता है। राजनीतिक दृष्टि से यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनावों के बाद विपक्षी गठबंधन की यह पहली औपचारिक बैठक थी, जिसमें भविष्य की रणनीति को लेकर गंभीर चर्चा हुई।

कांग्रेस की ओर से पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भाग लिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी, सांसद अभिषेक बनर्जी, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं की मौजूदगी ने बैठक को राजनीतिक रूप से और अधिक महत्व प्रदान किया। विभिन्न दलों के नेताओं ने अपने-अपने राज्यों के मुद्दों और राष्ट्रीय स्तर की चुनौतियों पर विचार रखते हुए साझा रणनीति पर जोर दिया।

बैठक में पांच प्रमुख मुद्दों पर व्यापक सहमति बनी। विपक्षी दलों ने निर्णय लिया कि महंगाई, बेरोजगारी और देश की आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार को लगातार घेरा जाएगा। नेताओं का मानना है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे आम जनता के जीवन से जुड़े हैं और जिन पर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक अभियान चलाया जा सकता है। इसके अलावा नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में सामने आई अनियमितताओं को लेकर भी केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया। विपक्ष ने एक बार फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई और कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक उठाया जाएगा।

बैठक में चुनावी प्रक्रियाओं और मतदाता अधिकारों से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। गठबंधन ने निर्णय लिया कि मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) तथा

मतदान अधिकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चिंता व्यक्त की जाएगी। विपक्षी नेताओं का कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करना सभी राजनीतिक दलों की साझा जिम्मेदारी है।

इंडिया ब्लॉक की सक्रियता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया कि अब गठबंधन की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाएंगी। तय किया गया कि हर दो महीने में सभी घटक दलों की बैठक होगी। इसी क्रम में अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय विपक्षी दलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और गठबंधन को सक्रिय बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा है।

बैठक में संसद के आगामी मानसून सत्र को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। विपक्षी नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि संसद के भीतर सभी दल साझा रणनीति के तहत सरकार को घेरेंगे। विभिन्न मुद्दों पर समन्वित तरीके से आवाज उठाने और विपक्ष की एकजुटता को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा। नेताओं का मानना है कि संसद में प्रभावी हस्तक्षेप के माध्यम से जनहित के मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाया जा सकता है।

हालांकि इस बैठक में कुछ प्रमुख सहयोगी दलों की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय बनी रही। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) और आम आदमी पार्टी ने बैठक में भाग नहीं लिया। विशेष रूप से दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजनीतिक दल डीएमके की अनुपस्थिति ने राजनीतिक पर्यवेक्षकों का ध्यान आकर्षित किया। इसी प्रकार आम आदमी पार्टी का बैठक से दूर रहना भी विपक्षी एकता को लेकर नए सवाल खड़े कर गया। हालांकि बैठक में मौजूद नेताओं ने इन अनुपस्थितियों को अधिक महत्व नहीं दिया और गठबंधन की एकजुटता पर जोर दिया।

बैठक में वामपंथी दलों और छोटे क्षेत्रीय संगठनों की सक्रिय भागीदारी भी देखने को मिली। विभिन्न नेताओं ने अपने विचार रखते हुए भाजपा के खिलाफ साझा संघर्ष को आगे बढ़ाने की आवश्यकता बताई। उनका कहना था कि लोकतांत्रिक संस्थाओं, सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों से जुड़े मुद्दों पर सभी विपक्षी दलों को मिलकर काम करना चाहिए। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मीडिया को संबोधित करते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि विपक्ष अब अधिक संगठित और आक्रामक भूमिका में दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष जारी रहेगा और सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए विपक्ष पूरी ताकत से काम करेगा। खरगे ने कहा कि गठबंधन के सभी दल इस बात पर सहमत हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और जनता की आवाज को बुलंद करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है।

खरगे ने विशेष रूप से नीट परीक्षा विवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि परीक्षा प्रणाली में बार-बार सामने आ रही गड़बड़ियां लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस विषय को गंभीरता से संभालने में विफल रही है और इसी कारण विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि विपक्ष अब केवल तात्कालिक राजनीतिक मुद्दों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि दीर्घकालिक रणनीति के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। नियमित बैठकों, साझा अभियानों और समन्वित संसदीय रणनीति की घोषणा को इसी दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। आने वाले वर्षों में यदि यह गठबंधन अपने आंतरिक मतभेदों को नियंत्रित कर पाता है और साझा एजेंडे पर टिके रहने में सफल रहता है, तो यह राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

दिल्ली में हुई इस बैठक ने स्पष्ट कर दिया है कि विपक्षी दल आगामी राजनीतिक संघर्ष को लेकर सक्रिय हो चुके हैं। 2029 का लोकसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक जमीन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

वीरता को राष्ट्र का नमन, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए जवानों व पुलिस अधिकारियों को मिला सम्मान

नई दिल्ली। राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और नागरिकों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना कर्तव्य निभाने वाले वीर सैनिकों और पुलिस अधिकारियों को सोमवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य रक्षा अलंकरण समारोह में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सशस्त्र बलों और पुलिस सेवाओं के उन जांबाज अधिकारियों एवं जवानों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में असाधारण साहस, अदम्य धैर्य और सर्वोच्च समर्पण का परिचय देते हुए राष्ट्र सेवा का गौरव बढ़ाया। समारोह में शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र जैसे प्रतिष्ठित वीरता अलंकरण प्रदान किए गए, जिनके माध्यम से देश ने अपने बहादुर नायकों को सम्मानपूर्वक नमन किया। राष्ट्रपति भवन का ऐतिहासिक प्रांगण उस समय गौरव और सम्मान की भावना से भर उठा जब देश के विभिन्न हिस्सों में वीरता और पराक्रम का प्रदर्शन करने वाले जवानों के नाम एक-एक कर पुकारे गए। समारोह केवल पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह उन साहसी व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक गाथाओं को याद करने का अवसर भी था, जिन्होंने राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्य का निर्वहन किया।

भारतीय सेना के मेजर आदित्य प्रताप सिंह को अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस और नेतृत्व क्षमता के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को अक्सर दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों, प्रतिकूल मौसम और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे वातावरण में मेजर आदित्य प्रताप सिंह ने जिस साहस और दक्षता का परिचय दिया, उसने उन्हें देश के सर्वोच्च वीरता सम्मानों में से एक का अधिकारी बनाया। उनके सम्मान ने सेना के युवा अधिकारियों और सैनिकों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है।

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जारी संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुलिस अधिकारियों को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस के निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर प्रसाद देशमुख को नक्सल विरोधी अभियानों में प्रदर्शित अदम्य साहस और उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए शौर्य चक्र प्रदान किया गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों का कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण माना जाता है, जहां हर अभियान जोखिम और अनिश्चितताओं से भरा होता है। इन अधिकारियों ने अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण निष्ठा और साहस दिखाते हुए कठिन अभियानों को सफल बनाया और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

समारोह में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला को भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। सिख रेजिमेंट की 19वीं बटालियन से जुड़े लेफ्टिनेंट कर्नल शुक्ला ने नियंत्रण रेखा के निकट आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान असाधारण वीरता का परिचय दिया था। अभियान के दौरान उन्होंने तीन आतंकवादियों को मार गिराते हुए अपने साथियों की सुरक्षा सुनिश्चित की और मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। उनकी बहादुरी और त्वरित निर्णय क्षमता ने उन्हें इस प्रतिष्ठित सम्मान का पात्र बनाया।

सहमति से बने संबंधों को चरित्र से जोड़ना गलत, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने छेड़ी नई बहस

नई दिल्ली। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वयस्कों की पसंद और सामाजिक नैतिकता के बीच संतुलन को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि दो अविवाहित वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध किसी व्यक्ति के चरित्र पर सवाल उठाने का आधार नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी केवल एक भर्ती विवाद तक सीमित नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक दृष्टिकोण और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े व्यापक विमर्श के रूप में देखा जा रहा है। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि कानून दो अविवाहित वयस्कों को आपसी सहमति से संबंध बनाने से नहीं रोकता और ऐसे संबंधों के आधार पर किसी व्यक्ति के नैतिक चरित्र के बारे में नकारात्मक धारणा बनाना उचित नहीं है।

न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह टिप्पणी उस मामले की सुनवाई के दौरान की, जिसमें एक उम्मीदवार की पुलिस कांस्टेबल पद पर नियुक्ति उसके अतीत के एक प्रेम संबंध से जुड़े आपराधिक मामले के कारण रद्द कर दी गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर कि किसी प्रेम संबंध

का अंत विवाह में नहीं हुआ, यह मान लेना कि किसी एक पक्ष ने दूसरे को धोखा दिया है, न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। अदालत ने कहा कि जीवन में अनेक रिश्ते बनते हैं और कई बार विभिन्न कारणों से वे विवाह तक नहीं पहुंच पाते। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर असफल संबंध में किसी प्रकार की आपराधिक मंशा या नैतिक दोष मौजूद था।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में व्यक्तिगत संबंधों के प्रति समाज में व्याप्त पूर्वाग्रहों पर भी अप्रत्यक्ष रूप से टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि दो वयस्क व्यक्तियों के बीच बने सहमति आधारित संबंधों को नैतिक पतन या खराब चरित्र का प्रमाण मानना उचित नहीं है। न्यायालय के अनुसार संविधान प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। जब तक कोई कार्य कानून के विरुद्ध नहीं है, तब तक केवल सामाजिक धारणाओं के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

मामला तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड से जुड़ा था। भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक उम्मीदवार का चयन पुलिस कांस्टेबल पद के लिए किया गया था, लेकिन बाद में उसके खिलाफ दर्ज एक पुराने आपराधिक मामले का हवाला देते हुए नियुक्ति रद्द कर दी गई। भर्ती बोर्ड का मानना था कि यह मामला उम्मीदवार के नैतिक चरित्र पर प्रश्नचिह्न लगाता है और उसे पुलिस सेवा जैसी अनुशासित एवं संवेदनशील जिम्मेदारी के लिए अनुपयुक्त बनाता है। हालांकि उम्मीदवार ने इस निर्णय को अदालत में चुनौती दी और कहा कि मामला एक निजी संबंध से जुड़ा था, जिसका निपटारा वर्षों पहले आपसी समझौते के माध्यम से हो चुका था।

सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि संबंधित महिला और उम्मीदवार एक-दूसरे के पड़ोसी थे तथा लगभग चार वर्षों तक उनके बीच संबंध रहे थे। बाद में दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हुए और मामला कानूनी विवाद तक पहुंच गया। हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और लोक अदालत में इसका निपटारा कर दिया गया। अदालत ने विशेष रूप से इस तथ्य पर ध्यान दिया कि मामले में बलपूर्वक संबंध स्थापित करने या किसी प्रकार की जबरदस्ती के प्रमाण सामने नहीं आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी मामले का लोक अदालत में समझौते के माध्यम से समाप्त होना अपराध स्वीकार करने के समान नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि यदि रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि समझौता दबाव, धमकी या बल प्रयोग के तहत कराया गया था, तो केवल समझौते के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। न्यायालय ने कहा कि नियोक्ता या भर्ती एजेंसी को भी ऐसे मामलों में संतुलित और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। फैसले में अदालत ने आपराधिक न्यायशास्त्र के एक मूल सिद्धांत को भी दोहराया। पीठ ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि अदालत में उसके खिलाफ आरोप सिद्ध न हो जाएं। केवल आरोप लग जाना या मामला दर्ज हो जाना किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बना देता। इसलिए नियुक्ति या रोजगार से जुड़े मामलों में भी इस सिद्धांत का सम्मान किया जाना चाहिए। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भविष्य में भर्ती प्रक्रियाओं और चरित्र सत्यापन से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। विशेष रूप से उन मामलों में, जहां किसी व्यक्ति के खिलाफ अतीत में निजी संबंधों से जुड़े विवाद दर्ज हुए हों, लेकिन अदालत में अपराध सिद्ध न हुआ हो। विशेषज्ञों के अनुसार यह फैसला इस बात पर जोर देता है कि व्यक्तिगत जीवन और पेशेवर योग्यता के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है तथा केवल सामाजिक या नैतिक धारणाओं के आधार पर किसी व्यक्ति के भविष्य को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए।

समाजशास्त्रियों का कहना है कि भारतीय समाज तेजी से बदल रहा है और व्यक्तिगत संबंधों को लेकर दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आ रहा है। ऐसे समय में सर्वोच्च अदालत की यह टिप्पणी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यह वयस्क व्यक्तियों की स्वायत्तता और उनकी निजी पसंद के अधिकार को मान्यता देती है।

दिल्ली में विपक्षी एकता की कवायद, उधर तृणमूल में बगावत का बिगुल; ममता के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजनीति में सोमवार का दिन उस समय बेहद नाटकीय मोड़ लेता दिखाई दिया जब एक ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख Mamata Banerjee दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ भाजपा के खिलाफ रणनीति तैयार करने में व्यस्त थीं, वहीं दूसरी ओर उनकी अपनी पार्टी के भीतर उभर रहे असंतोष ने खुली बगावत का रूप लेना शुरू कर दिया। राजधानी के राजनीतिक गलियारों में दिनभर जिस घटनाक्रम की सबसे अधिक चर्चा रही, वह तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के एक बड़े समूह द्वारा कथित रूप से भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के प्रति समर्थन जताने की पहल थी।

सूत्रों और विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इंडिया गठबंधन की बैठक के समानांतर तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद केंद्रीय मंत्री Bhupender Yadav के आवास पर पहुंचे, जहां महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा हुई। इस बैठक ने उस समय और अधिक राजनीतिक महत्व हासिल कर लिया जब पार्टी की वरिष्ठ

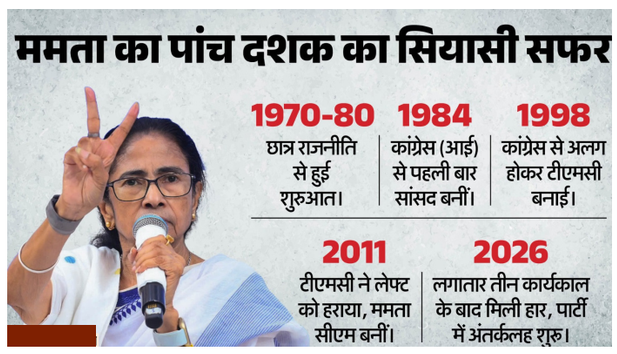

सांसद Kakoli Ghosh Dastidar ने दावा किया कि लगभग 20 सांसदों का एक समूह लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर एनडीए को समर्थन देने की इच्छा जता चुका है।

तृणमूल कांग्रेस के लिए यह घटनाक्रम साधारण राजनीतिक असहमति से कहीं अधिक गंभीर माना जा रहा है। पार्टी के भीतर लंबे समय से चल रहे असंतोष, संगठनात्मक मतभेदों और चुनावी झटकों की चर्चा पहले भी होती रही थी, लेकिन पहली बार यह असंतोष संसद के स्तर पर खुले राजनीतिक विद्रोह के रूप में सामने आता दिखाई दे रहा है। बागी सांसदों का दावा है कि वे केवल व्यक्तिगत नाराजगी के कारण नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीतिक दिशा को लेकर यह कदम उठा रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य एनडीए के साथ अधिक सुरक्षित और प्रभावी दिखाई देता है।

घटनाक्रम की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बागी गुट ने स्वयं को केवल असंतुष्ट सांसदों का समूह बताने के बजाय एक संगठित संसदीय धड़ा बनाने की बात कही है। रिपोर्टों के अनुसार, इस प्रस्तावित समूह में काकोली घोष दस्तीदार को मुख्य सचेतक तथा सांसद Shatabdi Roy को उपनेता की भूमिका देने की चर्चा सामने आई है। बागी सांसदों का दावा है कि वे लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष यह पक्ष रखने वाले हैं कि संसदीय स्तर पर वही वास्तविक बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि बागी गुट वास्तव में दो-तिहाई सांसदों का समर्थन जुटाने में सफल हो जाता है, तो दल-बदल कानून से जुड़े कई संवैधानिक और कानूनी प्रश्न भी सामने आ सकते हैं। यही कारण है कि पूरे मामले पर संसद, चुनावी राजनीति और संवैधानिक विशेषज्ञों की निगाहें टिकी हुई हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने तृणमूल कांग्रेस की आंतरिक स्थिति को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कभी ममता बनर्जी के सबसे मजबूत राजनीतिक किले के रूप में पहचानी जाने वाली पार्टी अब नेतृत्व और संगठनात्मक नियंत्रण की चुनौती का सामना करती दिखाई दे रही है। पिछले कुछ समय में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी, इस्तीफे और सार्वजनिक बयान पहले ही चर्चा का विषय रहे हैं। काकोली घोष दस्तीदार स्वयं भी हाल के महीनों में पार्टी नेतृत्व से मतभेदों को लेकर सुर्खियों में रही थीं।

दिल्ली में हुए इस घटनाक्रम का समय भी राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस समय इंडिया गठबंधन भाजपा के खिलाफ व्यापक विपक्षी एकता का संदेश देने की कोशिश कर रहा था, उसी समय गठबंधन के प्रमुख स्तंभों में से एक दल के भीतर इतना बड़ा संकट सामने आना विपक्षी राजनीति के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है। विपक्षी दल जहां केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे, वहीं तृणमूल कांग्रेस को अपने ही सांसदों की नाराजगी और संभावित विभाजन की चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर अंतिम और विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन पार्टी के भीतर बढ़ती हलचल को नजरअंदाज करना अब संभव नहीं माना जा रहा। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि आने वाले दिनों में लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज, सांसदों की वास्तविक संख्या और संवैधानिक प्रक्रियाएं इस विवाद की दिशा तय करेंगी। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में शुरू हुआ यह संकट अब राष्ट्रीय राजनीति का विषय बन चुका है। यदि बागी सांसद अपने दावों को संख्या बल के साथ साबित करने में सफल रहते हैं, तो यह तृणमूल कांग्रेस के इतिहास का सबसे बड़ा संसदीय विभाजन साबित हो सकता है। दूसरी ओर यदि पार्टी नेतृत्व इस संकट को नियंत्रित कर लेता है, तो यह ममता बनर्जी की राजनीतिक क्षमता और संगठन पर पकड़ का एक और उदाहरण माना जाएगा।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

कॉकरोच पार्टी के मुद्दों पर विचार की जरूरत

मुख्य न्यायाधीश की कॉकरोच वाली टिप्पणी के प्रतिरोध में व्यंग्यात्मक रूप में अस्तित्व में आई कॉकरोच जनता पार्टी ने आखिरकार आभासी दुनिया से निकलकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर दस्तक दे ही दी। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के दिल्ली पहुंचने और हजारों युवाओं की भागीदारी के बाद शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ प्रदर्शन समाप्त हो गया। सीजेपी का आरोप है कि नीट परीक्षा रद्द होने के बाद कई छात्रों ने आत्महत्या की है। पिछले दिनों सीजेआई द्वारा 'फेक डिग्री वाले युवाओं' की तुलना कॉकरोच से करने के बाद ऑनलाइन व्यंग्यात्मक आंदोलन के जमीन पर उतरने और विपक्षी दलों के समर्थन ने निश्चय ही सरकार की चिंता बढ़ाई है। ऑनलाइन मूवमेंट को लाखों युवाओं का समर्थन मिलने के बाद सरकार ने पहले सख्ती भी दिखायी थी। जंतर-मंतर के प्रदर्शन के बाद अभिजीत दीपके ने सरकार को सात दिन का समय देने की बात कही। साथ ही इसे महज एक ट्रेलर बताया है। उनकी दलील थी कि यह पार्टी योजनाबद्ध नहीं, स्वतःस्फूर्त पार्टी है और सरकार से नाराज हर छात्र की आवाज बनेगी। पार्टी ने देश में युवाओं को रोजगार न मिलने का आरोप भी लगाया। पार्टी का मानना है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था सुधारने में तो नाकाम रही ही है, लेकिन उन परीक्षाओं को भी पारदर्शी ढंग से आयोजित नहीं कर पा रही है, जो देश के लाखों युवाओं का भविष्य तय करते हैं। यह भी कि व्यवस्था की विफलता से लाखों युवाओं के सपने टूटे हैं, जो अब कॉकरोच को प्रतिरोध का प्रतीक बनाकर विरोध जता रहे हैं।

राजनीति के पंडित जंतर-मंतर में सीजेपी को प्रदर्शन के लिये अनुमति दिए जाने पर हैरानी जता रहे हैं। उनका मानना है कि पड़ोसी देशों में जेन ज़ी पर हुई सख्ती के बाद उग्र होने वाले आंदोलन सरकार को याद आए हैं, यही वजह है कि उसने कुछ उदारता बरती है। साथ ही यह भी कोशिश है कि देश के लाखों परिवारों से जुड़ा पेपर लीक का गुस्सा किसी तरह शांत हो जाए। यूं तो विषम आर्थिक परिस्थितियों में बेरोजगारी तो बढ़ी है, साथ ही रोजगार देने वाली व्यवस्था की विफलता देश के युवाओं को अशांत कर रही है। वे अपने भविष्य को लेकर खासे चिंतित हैं। इसीलिए शिक्षा और रोजगार देने वाली व्यवस्था का मुद्दा युवाओं को प्रभावित कर रहा है। विपक्षी राजनीतिक दल आरोप लगा रहे हैं कि यह आंदोलन युवा अशांति,जवाबदेही और असहमति की स्वतंत्रता का प्रतीक बन रहा है। तभी युवाओं ने हेय दृष्टि से देखे जाने वाले जीव कॉकरोच यानी तिलचट्टे को जीवटता के प्रतीक के रूप में परिभाषित किया है। यह बताने की कोशिश कि मुश्किल हालात में भी वे अपनी बात को रखते रहेंगे। युवाओं का मानना है कि पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अंकुश लगाना डिजिटल लोकतंत्र को नियंत्रित करने का प्रयास है। युवाओं की मांग है कि स्वस्थ लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त असहमति को शांतिपूर्ण ढंग से स्वीकार किया जाए। कहा जा रहा है कि कॉकरोच आंदोलन ने लोकतंत्र के सभी हितधारकों मसलन राजनीतिक वर्ग, नौकरशाही, न्यायपालिका तथा मीडिया को आत्मनिरीक्षण का मौका दिया है।

छोटी चीजों से आनंद और सुख की प्राप्ति

"प्रेम, त्याग और समर्पण के सहारे भी संपूर्णता तथा आनंद की अनुभूति हो जाती है। महत्व केवल दृष्टि का है। हम देखना क्या चाहते हैं।

अक्सर हमारे आम व्यवहार में यह सुनने को मिलता है-लीजिए यह मिठाई खाइए! नहीं-नहीं 'मन' नहीं है! पिक्चर चलते हैं। आज 'मन' नहीं है! या आज बाहर जाकर खाने का खूब 'मन' कर रहा है! गौर कीजियेगा, मन का अर्थ इच्छा से है। इच्छा, कामना, चाह यह सब 'मन' ही हैं। ये नहीं तो 'मन' भी नहीं है!! कामना ही कर्म की ओर प्रेरित करती है। कामनाएं असंख्य हो सकती हैं। देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बाहर जाकर खाने की कामना नहीं उठ सकती। कोई काम बिगड़ गया तो महफिल में जाने की चाह नहीं हो सकती!

इच्छाओं पर दृष्टि बनी रहे और सार्थक निरर्थक का भेद करना आ जाए, तो जीवन का कल्याण संभव है। अन्यथा, मनुष्य तो ताउम्र इनका गुलाम ही बना रहेगा। कामनाओं से मुक्ति यानी 'मन' की समाप्ति। और यही दशा परम-मुक्ति की आधारशिला बन सकती है। जीते जी परम मुक्ति! मरने के बाद, इस जीवन के संग्रहणों या बाधाओं से तो मुक्ति सभी को मिल ही जाती है। यह कोई विशेष उपलब्धि नहीं हो सकती! कुछ बहुत मौलिक जरूरतों के बीच ही लालसाएं पैदा होती हैं। इन लालसाओं का कोई अंत नहीं होता! एक कामना- खूब पैसा हो यानी जमीन-जायदाद, सोना-चांदी और बहुतायत में भोग सामग्री। दूसरी, नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा की। ख्याति ऐसी हो कि बच्चे-बड़े सभी आदर की दृष्टि से देखें। घर में सुख-शांति हो, सभी प्रसन्न रहें यह तीसरी ख्वाइश! शरीर स्वस्थ रहे, निरोगी हों। इससे अधिक मानव क्या चाहता है? इन्हीं कामनाओं के छोटे या विकराल और वीभत्स रूप ही तो परिलक्षित होते हैं।

आत्मोपलब्धि का मार्ग भी मन के रास्ते होकर ही गुजरता है। संसार में रमणातीत मानव स्वभाव अधिकांशतः यह कामना करता ही नहीं। करता भी है तो आधी-अधूरी। क्योंकि बहुत गहरे तो सांसारिक भोग की लिप्तता और लगातार पाते रहने की आकांक्षा ही उसे सुहाती है। इसलिए, बिना मन के किए गए समस्त आध्यात्मिक प्रयास विफल हो जाते हैं! कई स्मार्ट लोग अध्यात्म को भी सांसारिक चाहतों की पूर्ति से 'लिंक' कर देते हैं। नियमित पूजा-पाठ, सत्संग, मंदिर दर्शन, ध्यान और भक्ति को वे आत्मकल्याण के लिए नहीं, सांसारिक उपलब्धियों की प्राप्ति के उपक्रम की तरह इस्तेमाल करते हैं। धर्म का सहारा लेकर भी वे अपनी कर्मभूमि में अधार्मिक कार्यों में ही संलग्न रहते हैं। भ्रम यह रखते हैं कि अंत में दोनों समायोजित हो जाएंगे!

एक से अनेक हो जाने की एक तीव्र इच्छा से ईश्वर अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो गए। बस, एक तीव्र इच्छा ही तो कुंजी है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले श्रमण केवल एक ईमानदार और तीव्र इच्छा करें- आत्मोपलब्धी (परमात्मा प्राप्ति) की! शेष कार्य, यह इच्छा (मन) ही पूरा कर देगी। स्वयं को स्वयं से मिलाने का मार्ग मन ही निर्मित करता है। मजे की बात यह भी है कि यह मिलन करा देने के पश्चात मन विदा हो जाता है। मन की यह विदाई ही मुक्ति में परिवर्तित हो जाती है। मानव स्वभाव इच्छाओं के बारे में भी स्पष्ट नहीं है। उसे वाकई चाहिए क्या, इस पर ही वह भ्रमित है। दिखाता कुछ और है, लेकिन भीतर चाहतें कुछ अलग भूचाल मचाती हैं। संतुष्टि का स्वांग अवश्य करता है, लेकिन मरते दम तक कामनाओं के विकास में ही लगा रहता है। चाहतों की प्राथमिकता क्या हो, इतना भी ज्ञान नहीं, लेकिन समझता स्वयं को बड़ा बुद्धिमान है। पहला सुख निरोगी काया। प्राथमिकता की फेहरिस्त में यह अव्वल स्थान पर हो। रोगी और अस्वस्थ शरीर आत्मोपलब्धी के मार्ग में बड़ी बाधा पैदा कर सकता है। हां, एक बार उपलब्ध होने के उपरांत शारीरिक दुर्बलता मायने नहीं रखती, क्योंकि तदोपरांत आप शरीर के तल से ऊपर उठकर आत्मा के तल पर जी रहे होते हैं। लेकिन इस भूमिका तक पहुंच पाने के लिए शारीरिक तप और श्रम चाहिए, जो दुर्बलता से संभव नहीं है। स्वस्थ शरीर संयम और समय दोनों मांगता है। भागमभाग भरी जिंदगी में ज्यादातर के लिए यह संभव नहीं हो पा रहा। संभव होना मुश्किल भी नहीं है, बस प्राथमिकता में नहीं है!

लोगों की दूसरी प्राथमिकता है वित्तीय सुरक्षा। यहां बड़ा भारी पेच है! इसकी पूर्ति कभी पूरी होती ही नहीं, और समय रीत जाता है। सौ वर्षों की आयु तक हद से हद कितने रुपयों की आवश्यकता हो सकती है, यह गणित लगानी है। यह उतना मुश्किल भी नहीं है! मोटा-मोटी इसकी आपूर्ति सुनिश्चित होने के उपरांत, मानव जीवन के अन्य बड़े उद्देश्यों में स्वयं को खपाना चाहिए। भक्ति, सेवा, साधना या आत्मोथान। कोई भी मार्ग, जिससे 'मैं' यानी अहंकार के गलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो सके!

बहुत छोटी-छोटी चीजों से आनंद और सुख की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन, हमारी दृष्टि बड़ी चाहतों की आपूर्ति में लगी होने से छोटी खुशियों को लगभग नजरअंदाज कर देती हैं। चीजें ही क्यों, प्रेम, त्याग और समर्पण के सहारे भी संपूर्णता तथा आनंद की अनुभूति हो जाती है। महत्व केवल दृष्टि का है। हम देखना क्या चाहते हैं और महत्वपूर्ण आयामों को देखकर भी कितना अनदेखा कर जाते हैं! इच्छाओं के प्रति जागृति और कुछ महत्ती आध्यात्मिक इच्छाओं को पाने की भीतरी तड़प, बस इतना काफी है 'मन' के लिए। हाथ पकड़ कर नैय्या पार करा देगा!

प्रेरणा

बुद्धिमत्ता का सही अर्थ

जीवन में बुद्धिमत्ता को अक्सर केवल ज्ञान, शिक्षा या चतुराई से जोड़कर देखा जाता है। लोग मानते हैं कि जो व्यक्ति अधिक पढ़ा-लिखा है, जो कठिन समस्याओं का समाधान कर सकता है या जो अपने हितों को सुरक्षित रखने में सक्षम है, वही बुद्धिमान कहलाता है। किंतु वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। सच्ची बुद्धिमत्ता केवल अपने लिए सोचने में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और दूसरों के हितों के बीच संतुलन स्थापित करने में निहित होती है। जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार उचित निर्णय ले सके, अपने हितों की रक्षा भी करे और साथ ही दूसरों की आवश्यकताओं को भी समझे, वही वास्तव में बुद्धिमान कहलाने योग्य होता है।

एक राज्य में वर्षों तक सेवा देने के बाद वजीर ने अवकाश ग्रहण कर लिया। उसके पद के रिक्त होने पर बादशाह के सामने यह चुनौती थी कि राज्य के लिए ऐसा योग्य व्यक्ति चुना जाए जो केवल ज्ञानवान ही नहीं, बल्कि दूरदर्शी और संतुलित सोच वाला भी हो। इसलिए उसने अनेक उम्मीदवारों को आमंत्रित किया और कठिन परीक्षाओं के बाद तीन व्यक्तियों का चयन किया। अब अंतिम निर्णय लेना था, इसलिए बादशाह ने उनकी बुद्धिमत्ता को परखने के लिए एक सरल किंतु अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा।

उसने तीनों उम्मीदवारों से बारी-बारी कहा, "मान लो मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए, तो तुम क्या करोगे?" देखने में यह प्रश्न साधारण प्रतीत होता था, किंतु इसके भीतर नेतृत्व, जिम्मेदारी, स्वार्थ और कर्तव्य की गहरी परीक्षा छिपी हुई थी।

पहले उम्मीदवार ने तुरंत उत्तर दिया, "जहांपनाह, मैं सबसे पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा।" उसका उत्तर सुनने में अत्यंत विनम्र और निष्ठापूर्ण लगा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह अपने शासक के प्रति पूर्ण समर्पण रखता हो। किंतु यदि गहराई से विचार किया जाए तो उसका उत्तर व्यावहारिक नहीं था। यदि उसकी अपनी दाढ़ी भी जल रही हो और वह उसकी उपेक्षा करके केवल बादशाह की चिंता करे, तो संभव है कि वह स्वयं गंभीर रूप से घायल हो जाए। जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और सुरक्षा की पूरी तरह उपेक्षा करता है, वह लंबे समय तक दूसरों की सेवा भी नहीं कर सकता। अतः उसका उत्तर त्याग का प्रतीक तो था, लेकिन उसमें व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का अभाव था।

दूसरे उम्मीदवार ने कहा, "जहांपनाह, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा।" यह उत्तर पूरी तरह व्यावहारिक और स्वाभाविक लगा। हर व्यक्ति पहले अपने प्राणों और अपनी सुरक्षा की चिंता करता है। यदि स्वयं सुरक्षित रहेंगे, तभी दूसरों की सहायता कर पाएंगे। लेकिन इस उत्तर में एक समस्या थी। उसने केवल अपने हित को प्राथमिकता दी और बादशाह की स्थिति की कोई चिंता नहीं दिखाई। यह दृष्टिकोण आत्मरक्षा तो दर्शाता है, परंतु नेतृत्व और जिम्मेदारी की भावना को प्रकट नहीं करता। ऐसा व्यक्ति अपने हितों को सर्वोपरि मान सकता है और संकट के समय दूसरों की आवश्यकताओं को नजरअंदाज कर सकता है।

तीसरे उम्मीदवार ने कुछ क्षण सोचकर शांत स्वर में उत्तर दिया, "जहांपनाह, मैं एक हाथ से आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की।" उसका उत्तर सुनते ही बादशाह के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उसने उसी क्षण उसे वजीर नियुक्त कर दिया। बादशाह ने कहा, "जो अपनी आवश्यकता की उपेक्षा करता है, वह नादान है। जो केवल अपनी भलाई सोचता है, वह स्वार्थी है। किंतु जो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दूसरों का भी हित करता है, वही वास्तव में बुद्धिमान है।"

यह कथन केवल उस परीक्षा का निष्कर्ष नहीं था, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी था। संसार में अधिकांश समस्याएं इसी कारण उत्पन्न होती हैं क्योंकि लोग या तो अत्यधिक स्वार्थी हो जाते हैं या फिर अपनी आवश्यकताओं की इतनी उपेक्षा करते हैं कि स्वयं ही असहाय बन जाते हैं। दोनों ही स्थितियां संतुलन के अभाव को दर्शाती हैं। सच्ची बुद्धिमत्ता संतुलन में है। आज के समय में भी यह शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस काल में थी। एक परिवार का मुखिया यदि केवल अपने आराम और इच्छाओं के बारे में सोचे, तो परिवार की आवश्यकताएं अधूरी रह जाएंगी। दूसरी ओर यदि वह केवल परिवार के लिए जीते हुए अपनी सेहत और मानसिक शांति की उपेक्षा कर दे, तो एक दिन वह स्वयं कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि वह अपने स्वास्थ्य और आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए परिवार की जिम्मेदारियों को भी निभाए।

इसी प्रकार किसी संगठन का नेता यदि केवल कर्मचारियों के हितों की बात करे और संस्था की आर्थिक स्थिति की अनदेखी करे, तो संगठन टिक नहीं पाएगा। वहीं यदि वह केवल लाभ कमाने पर ध्यान दे और कर्मचारियों की भलाई की चिंता न करे, तो संस्था में असंतोष फैल जाएगा। एक सफल नेता वही होता है जो दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाए रखे।

मानव जीवन में संतुलन का महत्व अत्यंत बड़ा है। प्रकृति भी हमें यही शिक्षा देती है। सूर्य केवल प्रकाश ही नहीं देता, वह ताप भी देता है। वर्षा केवल जल ही नहीं लाती, वह मौसम का संतुलन भी बनाए रखती है। यदि किसी एक तत्व की अधिकता या कमी हो जाए, तो जीवन प्रभावित हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

वास्तविक बुद्धिमत्ता का अर्थ केवल तीव्र बुद्धि या अधिक ज्ञान नहीं है। यह सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता है। यह समझने की शक्ति है कि कब स्वयं की रक्षा करनी है और कब दूसरों की सहायता करनी है। यह वह कला है जो व्यक्ति को स्वार्थ और त्याग की चरम सीमाओं से बचाकर मध्य मार्ग पर चलना सिखाती है।

जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, वह समाज में सम्मान नहीं पा सकता। जो केवल दूसरों के लिए जीते हुए स्वयं को नष्ट कर देता है, वह भी लंबे समय तक उपयोगी नहीं रह सकता। लेकिन जो अपने कर्तव्यों और आवश्यकताओं के बीच सामंजस्य स्थापित कर लेता है, वही जीवन में सफलता, सम्मान और संतोष प्राप्त करता है।

इस कथा का संदेश अत्यंत सरल किंतु गहरा है। बुद्धिमत्ता का अर्थ केवल सोचने की क्षमता नहीं, बल्कि संतुलित सोच की क्षमता है। जो व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित रखते हुए दूसरों का भी हित कर सके, जो अपने कर्तव्य और करुणा दोनों को साथ लेकर चले, और जो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखे, वही वास्तविक अर्थों में बुद्धिमान कहलाने का अधिकारी है। यही सच्ची नेतृत्व क्षमता है, यही जीवन की सफलता का आधार है और यही मानवता का सर्वोत्तम स्वरूप भी है।

होर्मुज की बिसात पर ट्रंप को मात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 मई को इंटरनेट मीडिया पर अपनी एक पोस्ट में दावा किया था कि ईरान के साथ शांति समझौते पर सहमति लगभग बन चुकी है, जिसमें होर्मुज जलमार्ग का खुलना भी शामिल है। इस बात को करीब दो हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन न समझौता हुआ है और न होर्मुज खुला है। कभी ट्रंप कहते हैं कि वे ईरान के प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं। कभी कहते हैं वे उनसे संतुष्ट नहीं हैं। कभी कहते हैं उन्हें कोई जल्दी नहीं है। कभी कहते हैं कि समझौते के लिए ईरानी अयातुल्ला से भी मिलना पड़े तो वे तैयार हैं। कभी दूसरे देशों से कहते हैं कि होर्मुज खुलवाने में मदद करें। कभी कहते हैं उन्हें किसी की जरूरत नहीं है।

कूटनीति और रणनीति के जानकार भी इसे लेकर असमंजस में हैं। कुछ का मानना है कि युद्ध में जितनी हार-जीत होनी थी, वह हो चुकी। अब होर्मुज बंद रहने की चोट कौन कितनी देर तक बर्दाश्त कर पाता है, इसकी आजमाइश चल रही है। दुनिया के 38 विकसित लोकतंत्रों के संगठन ओईसीडी ने इसके चलते आर्थिक संकट की चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यदि एक महीने के भीतर होर्मुज नहीं खुला तो दुनिया की अर्थव्यवस्था दो साल के लिए धीमी पड़ जाएगी। दुनिया की आर्थिक विकास दर 3.4 प्रतिशत से घटकर इस वर्ष 2.1 प्रतिशत रह जाने और अगले वर्ष 1.8 प्रतिशत रह जाने की आशंका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी विकास दर के अनुमान को 6.9 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत और महंगाई की दर का अनुमान बढ़ाकर 5.1 प्रतिशत कर लिया है। अमेरिका में भी पहली तिमाही के आधार पर विकास दर 1.6 प्रतिशत आंकी जा रही है, जबकि महंगाई दर 3.8 प्रतिशत पर जा पहुंची है, जो अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की सहजता के अनुमान से लगभग दोगुनी है। तेल के दाम भी दोगुने हो चुके हैं और उसकी आपूर्ति भी बाधित है। यह सब देखकर ईरान को लगता है कि जैसे-जैसे नवंबर के मध्यावधि चुनाव नजदीक आएंगे, वैसे-वैसे ट्रंप का धीरज डगमगाएगा और वे उसकी शर्तों पर समझौते को बेबस हो जाएंगे।

दूसरी ओर, ट्रंप को लगता है कि ईरानी लोगों की सहनशक्ति पहले जवाब देगी। वहां हर चीज की किल्लत हो चुकी है और महंगाई की दर 77 प्रतिशत से ऊपर चली गई है। एक डालर 18 लाख रियाल का हो गया है। होर्मुज की नाकेबंदी के कारण ईरान अपना तेल नहीं बेच पा रहा, जिसे तेल भंडारों और तेल के जहाजों में जमा किया जा रहा है, लेकिन ऐसी भंडारण क्षमताओं की भी एक सीमा है। उनके भर जाने के बाद तेल निकालना रोकना होगा। रोकने पर कुओं में हवा भर सकती है और वे बंद हो सकते हैं। इसलिए देर-सबेर उसे अमेरिका की शर्तें मानने को विवश होना पड़ेगा। वहीं, ईरानी विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही करीब 125 अरब बैरल तेल जहाजों में भरकर मलेशिया और चीन के तटों के समीपवर्ती समुद्र में भेज दिया था, ताकि वे अमेरिका के हाथ न लगें। ईरान उस तेल को बेचकर तीन-चार महीने और गुजार सकता है।

इस क्रम में इजरायली विशेषज्ञों का मानना है कि गतिरोध की असली जड़ नेतन्याहू हैं। वे नहीं चाहते कि ईरान का 465 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम जब्त किए बिना और हिजबुल्ला और हाउती जैसे प्यादे संगठनों की जड़ें उखाड़े बिना ट्रंप कोई शांति समझौता कर बैठें। इसलिए वे ट्रंप के बार-बार युद्धविराम के एलान के बावजूद अपने हमले नहीं रोक रहे हैं। वे हिजबुल्ला को ईरान से भी बड़ा खतरा मानते हैं, क्योंकि ईरान तो हजार किलोमीटर दूर है, लेकिन हिजबुल्ला तो ऐन इजरायल की सीमा पर है। ईरान के लिए हिजबुल्ला ऐसा हथियार है जिसके सहारे उसने लेबनान को उपनिवेश जैसा बना लिया है और वहां से इजरायल और सीरिया दोनों पर अंकुश रखता है। यहां संभव यह भी है कि नेतन्याहू ट्रंप की मिलीभगत से ही हिजबुल्ला का हमास जैसा हाल करने पर तुले हों। ईरान पर संवर्धित यूरेनियम उनके हवाले करने और होर्मुज जलमार्ग खोलने का दबाव बढ़ाने के लिए यह चाल चली जा रही हो।

जो भी हो, अब तो अमेरिका के दक्षिणपंथी रणनीतिकार भी मानने लगे हैं कि इस युद्ध में ट्रंप मात खा गए हैं। ब्रूकिंग्स संस्थान के वरिष्ठ सदस्य और नव-अमेरिकी शताब्दी परियोजना के सह संस्थापक राबर्ट केगन के लेख-'चेकमेट इन ईरान' की काफी चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने ईरान युद्ध को अमेरिकी रणनीति की सबसे बड़ी हार सिद्ध किया है। उनका तर्क है कि 37 दिनों के हवाई हमलों से ईरान के शीर्ष नेतृत्व और सैन्य क्षमता का बड़ी हद तक क्षय करके भी अमेरिका उससे कोई बड़ी रियायत लेने में नाकाम रहा है। ईरान न तो संवर्धित यूरेनियम देने को तैयार है, न परमाणु संवर्धन का अधिकार छोड़ने को और न ही प्यादे संगठनों का समर्थन बंद करने को। ऊपर से उसने होर्मुज जलमार्ग पर अपना अधिकार और जमा लिया है जिसकी वजह से पूरे विश्व में ऊर्जा का और आर्थिक विकास की दर धीमी पड़ने का संकट खड़ा हो गया है।

विश्व का एक चौथाई तेल, पांचवें हिस्से की गैस, एक तिहाई उर्वरक, आधा सल्फर और एक तिहाई हीलियम होर्मुज से गुजरते हैं। इसका बंद होना विश्व आपूर्ति तंत्र के समक्ष अब तक की सबसे गंभीर रुकावट है, जिसे ट्रंप चाहकर भी खुलवा नहीं पा रहे हैं। केगन का मानना है कि इस युद्ध में अमेरिका की साख पर सबसे बड़ा आघात हुआ है। ईरान ने अपने सस्ते और कामचलाऊ हथियारों से साबित कर दिया कि अमेरिका की अरबों-खरबों के शस्त्रास्त्रों से लैस महाबली सेना खाड़ी के मित्र देशों की रक्षा करना तो दूर अपने ठिकानों की रक्षा भी नहीं कर पाई।

अभियान

द्रोणागिरी की अमर गाथा : जहां पर्वत, परंपरा और विश्वास का अनूठा संगम है

भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में हिमालय का स्थान सदैव सर्वोच्च रहा है। यह केवल बर्फ से ढके पर्वतों की श्रृंखला नहीं, बल्कि अनगिनत कथाओं, मान्यताओं, ऋषियों की तपस्थली और दिव्य रहस्यों का जीवंत प्रतीक है। सदियों से हिमालय भारतीय जनमानस की आस्था का केंद्र रहा है। इसकी गोद में बसे अनेक स्थान ऐसे हैं, जिनका उल्लेख पौराणिक ग्रंथों, लोककथाओं और धार्मिक परंपराओं में मिलता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित द्रोणागिरी पर्वत और संजीवनी शिखर भी ऐसे ही स्थलों में शामिल हैं, जिनका नाम सुनते ही रामायण की प्रसिद्ध कथा, संजीवनी बूटी और हनुमानजी की अद्भुत यात्रा स्मरण हो उठती है।

द्रोणागिरी का उल्लेख भारतीय संस्कृति में केवल एक पर्वत के रूप में नहीं, बल्कि जीवनदायिनी शक्ति और चमत्कारी औषधियों के स्रोत के रूप में किया जाता है। रामायण के अनुसार लंका युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण पर शक्ति बाण का प्रहार किया, तब वे गंभीर रूप से घायल होकर मूर्छित हो गए। युद्धभूमि में उपस्थित वैद्य सुषेण ने भगवान राम को बताया कि लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए हिमालय स्थित द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लानी होगी। यह कार्य अत्यंत कठिन था क्योंकि समय बहुत कम था और लक्ष्मण के जीवन की डोर क्षीण होती जा रही थी।

भगवान राम के आदेश पर हनुमानजी तत्काल हिमालय की ओर रवाना हुए। जब वे द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो वहां असंख्य दुर्लभ जड़ी-बूटियां और वनस्पतियां थीं। संजीवनी बूटी की सही पहचान करना उनके लिए संभव नहीं हो पाया। समय तेजी से बीत रहा था और युद्धभूमि में सभी की निगाहें उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। ऐसी परिस्थिति में हनुमानजी ने अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने पूरा पर्वतखंड ही उखाड़ लिया और उसे लेकर लंका की ओर उड़ चले। यही वह प्रसंग है जिसने द्रोणागिरी पर्वत को भारतीय धार्मिक चेतना में अमर बना दिया। स्थानीय लोकमान्यताओं के अनुसार हनुमानजी जब पर्वतखंड लेकर जा रहे थे, तब उन्होंने मार्ग में एक स्थान पर कुछ समय विश्राम किया था। वर्तमान में वही स्थान संजीवनी शिखर के नाम से प्रसिद्ध है। समुद्र तल से लगभग साढ़े दस हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान आज श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहां पहुंचने पर दूर-दूर तक फैले हिमालयी पर्वत, शीतल वातावरण और प्राकृतिक शांति मन को आध्यात्मिक अनुभूति से भर देते हैं। यहां स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना यहां अवश्य फल देती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

द्रोणागिरी पर्वत से जुड़ी सबसे अनोखी बात वहां की स्थानीय धार्मिक परंपराएं हैं। जहां देश के अधिकांश भागों में हनुमानजी की पूजा अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाती है, वहीं द्रोणागिरी गांव के लोगों की मान्यता कुछ भिन्न है। गांव के निवासी पर्वत देवता को अपना आराध्य मानते हैं। उनके अनुसार द्रोणागिरी केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि जीवन और प्रकृति का रक्षक है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि जब हनुमानजी पर्वत का एक हिस्सा अपने साथ ले गए, तब पर्वत को क्षति पहुंची थी। इस घटना की स्मृति आज भी उनकी लोक परंपराओं में जीवित है।

द्रोणागिरी गांव के लोग स्वयं को प्रकृति उपासक सनातन धर्मावलंबी मानते हैं। उनके लिए पर्वतराज हिमालय देवस्वरूप हैं और जीवनदायिनी शक्तियों के संरक्षक भी। गांव में किसी भी शुभ कार्य, धार्मिक आयोजन या संकट की घड़ी में पर्वत देवता का स्मरण किया जाता है। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और आज भी लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। यही कारण है कि द्रोणागिरी गांव भारतीय लोकसंस्कृति का एक अनूठा उदाहरण माना जाता है।

इस गांव की एक विशेष पहचान इसकी रामलीला परंपरा भी है। देश के अधिकांश हिस्सों में रामलीला का आयोजन कई दिनों तक चलता है, लेकिन द्रोणागिरी गांव में इसका मंचन केवल तीन दिनों तक किया जाता है। यह परंपरा स्थानीय मान्यताओं और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई है। गांव के लोग अपनी परंपराओं को आज भी उसी श्रद्धा और सम्मान के साथ निभाते हैं, जैसे उनके पूर्वज निभाते आए थे। यह सांस्कृतिक विशिष्टता द्रोणागिरी को अन्य हिमालयी गांवों से अलग पहचान प्रदान करती है।

द्रोणागिरी पर्वत का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि औषधीय संपदा के कारण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से ही इसे दुर्लभ जड़ी-बूटियों का भंडार माना जाता रहा है। आयुर्वेदिक ग्रंथों और स्थानीय परंपराओं में इस क्षेत्र का उल्लेख अनेक औषधीय वनस्पतियों के स्रोत के रूप में मिलता है। यहां की जलवायु, ऊंचाई और प्राकृतिक परिस्थितियां ऐसी हैं जो कई महत्वपूर्ण वनस्पतियों के विकास के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि आज भी इस क्षेत्र में अनेक ऐसी जड़ी-बूटियां मौजूद हैं जिनके औषधीय गुणों का पूरा वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो पाया है।

संजीवनी बूटी की खोज आज भी शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। विभिन्न अध्ययनों में कई वनस्पतियों को संजीवनी से जोड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है। फिर भी द्रोणागिरी पर्वत और संजीवनी की कथा लोगों की आस्था में उतनी ही जीवंत बनी हुई है जितनी सदियों पहले थी। यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि यहां इतिहास, विश्वास और लोकपरंपराएं एक-दूसरे के साथ मिलकर जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। स्थानीय ग्रामीणों के बीच एक और रोचक मान्यता प्रचलित है। उनका विश्वास है कि हनुमानजी ने पर्वत को हुई क्षति के लिए वापस आने का वचन दिया था। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि आज भी समय-समय पर कुछ विशेष वानर इस क्षेत्र में दिखाई देते हैं, जिन्हें हनुमानजी का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग उन्हें देख पाने का दावा करते हैं, जबकि कुछ लोगों को उनके दर्शन नहीं होते। चाहे इन मान्यताओं का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण न हो, लेकिन स्थानीय समाज में इनका विशेष महत्व है और ये लोकविश्वास पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ते आ रहे हैं।

समय के साथ द्रोणागिरी और संजीवनी शिखर धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु, प्रकृति प्रेमी, पर्वतारोही और शोधकर्ता यहां पहुंचते हैं। कोई रामायण से जुड़ी स्मृतियों को महसूस करने आता है, कोई हिमालय की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता देखने आता है और कोई यहां की दुर्लभ वनस्पतियों का अध्ययन करने आता है। इन स्थलों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और इनके कारण स्थानीय लोगों को रोजगार तथा आर्थिक अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं।

द्रोणागिरी और संजीवनी शिखर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां आस्था और प्रकृति एक-दूसरे में विलीन दिखाई देती हैं। यहां आने वाला व्यक्ति केवल एक पर्वत या मंदिर नहीं देखता, बल्कि वह उस सांस्कृतिक विरासत को महसूस करता है जिसने सदियों से भारतीय समाज को प्रेरित किया है। यहां की हवाओं में लोककथाओं की गूंज सुनाई देती है, पर्वतों में इतिहास की स्मृतियां जीवित प्रतीत होती हैं और प्रकृति के प्रत्येक दृश्य में अध्यात्म की अनुभूति होती है।

आज भी द्रोणागिरी पर्वत और संजीवनी शिखर भारतीय जनमानस के लिए श्रद्धा, विश्वास और जिज्ञासा के केंद्र बने हुए हैं। ये स्थल हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत केवल ग्रंथों और मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्वतों, जंगलों, गांवों और लोकमान्यताओं में भी समान रूप से जीवित है। हिमालय की गोद में बसे ये पवित्र स्थान भारतीय संस्कृति की उस अमर परंपरा का प्रतीक हैं, जहां प्रकृति, आस्था और इतिहास मिलकर एक ऐसी विरासत का निर्माण करते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

'मेरी कंपनी' नहीं, 'हमारी कंपनी' की सोच अपनाइए: सूरत के उद्यमियों को डॉ. आनंद देशपांडे का सफलता मंत्र

सूरत। तेजी से बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती भूमिका और तकनीक आधारित कारोबार के नए दौर में सफल उद्यमिता के सूत्र क्या हैं, इस विषय पर सूरत के प्रमुख उद्यमियों को एक विशेष संवाद कार्यक्रम में उद्योग जगत के दिग्गज और परसिस्टेंट सिस्टम्स के संस्थापक एवं चेयरमैन डॉ. आनंद देशपांडे से सीधे संवाद का अवसर मिला। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) तथा इंटीग्रिटी नेटवर्क के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 'आस्क मी एनीथिंग' कार्यक्रम में 50 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले उद्यमियों ने भाग लिया और व्यवसाय विस्तार, नेतृत्व, वैश्विक प्रतिस्पर्धा तथा तकनीकी परिवर्तन जैसे विषयों पर खुलकर चर्चा की।

कार्यक्रम में उपस्थित उद्यमियों को संबोधित करते हुए डॉ. देशपांडे ने कहा कि किसी भी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए केवल पूंजी या तकनीक पर्याप्त नहीं होती, बल्कि स्पष्ट दृष्टिकोण, दीर्घकालिक लक्ष्य, मजबूत नेतृत्व और सक्षम टीम संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि व्यवसाय की सफलता का वास्तविक आधार यह है कि संस्थापक अपने संगठन को केवल निजी स्वामित्व की दृष्टि से न देखें, बल्कि उसे सामूहिक प्रयास और साझा जिम्मेदारी का मंच मानें। उन्होंने उद्यमियों को सलाह दी कि व्यवसाय की वृद्धि के साथ-साथ सोच का दायरा भी बढ़ना चाहिए। यदि कोई उद्यमी हर निर्णय को केवल अपनी कंपनी और अपने लाभ के दृष्टिकोण से देखता है तो उसकी विकास यात्रा सीमित रह सकती है। इसके विपरीत यदि वह कर्मचारियों, साझेदारों और ग्राहकों को साथ लेकर चलता है तो संगठन अधिक मजबूत और टिकाऊ बनता है। उन्होंने कहा कि "मेरी कंपनी" की मानसिकता से बाहर निकलकर "हमारी कंपनी" का दृष्टिकोण अपनाना ही आधुनिक कॉर्पोरेट सफलता का मूल मंत्र है।

डॉ. देशपांडे ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि कर्मचारियों को केवल वेतनभोगी कार्यकर्ता नहीं समझना चाहिए। उन्हें संगठन के विकास में भागीदार बनाने की संस्कृति विकसित करनी होगी। उन्होंने कहा कि आज दुनिया की कई सफल कंपनियां अपने कर्मचारियों को इक्विटी और ईएसओपी (एम्प्लॉयी स्टॉक ओनरशिप प्लान) जैसे विकल्प देकर उन्हें कंपनी की सफलता से सीधे जोड़ रही हैं। इससे कर्मचारियों में स्वामित्व की भावना विकसित होती है और वे संगठन की प्रगति के लिए अधिक समर्पण के साथ कार्य करते हैं।

व्यवसायिक रणनीति पर चर्चा करते हुए उन्होंने उद्यमियों को बड़े बाजारों में छोटी हिस्सेदारी हासिल करने की दौड़ से बचने की सलाह दी। उनका कहना था कि उद्यमियों को ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों या निच मार्केट की पहचान करनी चाहिए जहां वे प्रभावी नेतृत्व स्थापित कर सकें। यदि कोई कंपनी किसी विशेष क्षेत्र में 20 प्रतिशत या उससे अधिक बाजार हिस्सेदारी हासिल कर लेती है तो वह उस क्षेत्र में प्रभावशाली खिलाड़ी बन सकती है। इससे ब्रांड पहचान मजबूत होती है और दीर्घकालिक विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।

कार्यक्रम के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे अधिक चर्चा का विषय रहा। डॉ. देशपांडे ने कहा कि एआई तकनीक केवल एक नया उपकरण नहीं है, बल्कि यह व्यापार और उद्योग की पूरी संरचना को बदलने की क्षमता रखती है। उन्होंने बताया कि कोडिंग, डेटा विश्लेषण और अनेक तकनीकी कार्यों में एआई तेजी से मानव क्षमताओं को चुनौती दे रहा है। ऐसे में केवल मैन-आवर्स बेचने या पारंपरिक कोडिंग सेवाओं पर आधारित व्यवसाय मॉडल भविष्य में दबाव का सामना कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में कंपनियों को अपने व्यवसाय मॉडल में बड़े बदलाव करने होंगे। केवल समय के आधार पर सेवाएं बेचने के बजाय परिणाम आधारित मूल्य निर्धारण मॉडल अपनाने की आवश्यकता होगी। ग्राहक अब केवल यह नहीं देखेंगे कि किसी काम में कितने घंटे लगे, बल्कि यह देखेंगे कि उस काम से उन्हें क्या परिणाम प्राप्त हुआ। इसलिए कंपनियों को अपनी सेवाओं और उत्पादों को परिणाम-केंद्रित बनाना होगा।

डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे पर भी उन्होंने महत्वपूर्ण विचार रखे। उनका कहना था कि जैसे-जैसे एआई का उपयोग बढ़ेगा, वैसे-वैसे सुरक्षित और निजी डेटा आधारित एआई समाधानों की मांग भी बढ़ेगी। आने वाले समय में एआई एजेंट्स, प्राइवेट एआई मॉडल और सुरक्षित डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी उद्योग के सबसे तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्रों में शामिल होंगे। उन्होंने उद्यमियों से आग्रह किया कि वे इन क्षेत्रों में निवेश और नवाचार की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार करें।

विदेशी बाजारों में विस्तार के विषय पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में डॉ. देशपांडे ने अपनी चर्चित "बफ़ेलो स्ट्रैटेजी" का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नई कंपनियों को हर बार नया बाजार तैयार करने में अपनी ऊर्जा और संसाधन खर्च नहीं करने चाहिए। इसके बजाय उन्हें पहले से स्थापित वैश्विक प्लेटफॉर्म्स और इकोसिस्टम का हिस्सा बनने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि Salesforce, Microsoft और AWS जैसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर कंपनियां लाखों संभावित ग्राहकों तक आसानी से पहुंच बना सकती हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय विस्तार की प्रक्रिया सरल, तेज और अधिक प्रभावी बन जाती है।

कार्यक्रम के दौरान सूरत की उन कंपनियों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने पिछले चार वर्षों में अपने व्यवसाय में दस गुना वृद्धि हासिल की है। वसुंधरा इन्फोटेक, डिज़ाइनविज़ और एक प्रमुख ई-कॉमर्स एग्रीगेटर को विशेष सम्मान प्रदान किया गया। इन कंपनियों के संस्थापकों ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि किस प्रकार उन्होंने चुनौतियों का सामना करते हुए विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल किया। उनके अनुभवों ने उपस्थित उद्यमियों को प्रेरित किया और व्यावहारिक सीख प्रदान की।

कार्यक्रम में उद्योग जगत से जुड़े कई प्रतिष्ठित व्यक्तित्व उपस्थित रहे। एसजीसीसीआई के ऑनरेरी ट्रेज़रर अतुल पटेल, डॉ. अनिल सरावगी और डॉ. विजय रादड़िया सहित अनेक उद्योग प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। सभी ने इस प्रकार के संवाद मंचों की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि बदलते तकनीकी और वैश्विक परिदृश्य में उद्यमियों को निरंतर सीखते रहने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम के आयोजकों चेतन पटेल, पुनीत गजेरा, अमर पांचाल, नीरव अलगिया, सौमिश काकड़िया और गणपत धमेलिया ने कहा कि सूरत केवल व्यापारिक शहर ही नहीं, बल्कि नवाचार और तकनीकी उद्यमिता का उभरता हुआ केंद्र भी बन रहा है। ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों को वैश्विक सोच, आधुनिक तकनीक और भविष्य के व्यापारिक अवसरों से जोड़ना है।

एसजीसीसीआई के नए अध्यक्ष अशोक जिरावाला वस्त्र उद्योग से चैंबर नेतृत्व तक का एक सफल सफर

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत के कपड़ा बाजार, राजनीति और सामाजिक हलकों में एक जाना-पहचाना नाम अशोक जीरावाला को सर्वसम्मति से दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (एसजीसीसीआई) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिससे कपड़ा बाजार समेत उनके मित्रों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है।

अब आइए वाणिज्य मंडल के कार्यों पर एक नज़र डालते हैं। यह उद्योग जगत को सूचित रखने और उसकी समस्याओं से अवगत कराकर उसकी सहायता करने के लिए भी उत्तरदायी है। इसे उद्योगों, निर्यात और व्यापार में गैस संबंधी मुद्दों पर सरकार से चर्चा करनी होती है और भारत सहित अन्य देशों में उद्योग से संबंधित नई आर्थिक नीतियों पर वैश्विक स्तर पर विचार-विमर्श करना होता है।

आइए यहां अशोक जीरावाला के बारे में बात करते हैं, जो चैंबर के अध्यक्ष चुने गए हैं और जिनका मुख्य व्यवसाय वस्त्र उद्योग है। यानी उनका वस्त्र बाजार से सीधा संबंध है और इसी वजह से अशोक जीरावाला अपने हंसमुख और खुले स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं, जिसकी वजह से वस्त्र बाजार के व्यापारियों में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है। ये अशोक जीरावाला मूल रूप से सौराष्ट्र के निवासी हैं, यानी काठियावाड़ के निवासी, यानी सौराष्ट्र पाटीदार समुदाय से हैं। वे (अशोकभाई) 2011 में सूरत नगर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और संगठन को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके अनुभव की बात करें तो वे 1982 में सेवा दल के सदस्य थे। 1985 में वे युवा कांग्रेस के कार्यकारी सदस्य भी रहे। इसके अलावा, वे 1994 से 2002 तक सूरत जिला युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रहे और उन्होंने अच्छा काम किया।

वे वर्तमान में विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं। जैसे कि फेडरेशन गुजरात वीवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, वराछा कपोदरा वीवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, योगा स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एसोसिएशन के ट्रस्टी। वर्तमान की बात करें तो, 2025 से 2026 तक, 23 अप्रैल 2026 को उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उद्योगों में गैस आपूर्ति पर चर्चा की। उन्होंने पीएम मित्रा पार्क पर भी बात की। 25 अप्रैल 2026 को उन्होंने मध्य पूर्व पर भाषण दिया और नए वैश्विक बाजार के बारे में चर्चा की।

30 अप्रैल 2026 को भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के सेमिनार में कहा गया कि सूरत टेक्सटाइल्स को ब्रिटेन के बाजार में लाभ होगा। 1 सितंबर 2025 को जब गुजरात के वित्त मंत्री से मुलाकात कर जी.आई.सी.डी., आईटीसी रिफंड और कपड़ा सब्सिडी की मांग करके उद्योग को जीवित रखने का प्रयास करने वाले अशोक जीरावाला को चैंबर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष चुना गया, तो उनके करीबी मित्र और मीडिया जगत से जुड़े एक सामाजिक संगठन के सदस्य छगनलाल मेवाड़ा ने उन्हें पगड़ी पहनाकर और फूलों का गुलदस्ता भेंट करके बधाई दी। इसके साथ ही, रविराज देसाई को चैंबर ऑफ कॉमर्स का उपाध्यक्ष, परेशभाई लाठिया को सचिव और अतुलभाई पटेल को कोषाध्यक्ष चुना गया। छगनलाल मेवाड़ा की ओर से इन सभी को बधाई दी गई।

असम कैबिनेट में जिम्मेदारियों का नया समीकरण, अहम मंत्रालय अपने पास रखकर हिमंत सरमा ने दिए स्पष्ट संकेत

गुवाहाटी। असम की राजनीति में सोमवार का दिन महत्वपूर्ण प्रशासनिक और राजनीतिक संदेशों से भरा रहा, जब मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंत्रिपरिषद के विस्तार के बाद नए मंत्रियों के बीच विभागों का औपचारिक बंटवारा कर दिया। इस निर्णय के साथ राज्य सरकार की कार्यप्रणाली, नेतृत्व की प्राथमिकताओं और आगामी राजनीतिक रणनीति की तस्वीर भी काफी हद तक स्पष्ट हो गई है। मुख्यमंत्री ने जहां एक ओर कई अनुभवी मंत्रियों पर अपना भरोसा बरकरार रखा, वहीं दूसरी ओर कुछ नए और उभरते नेताओं को महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी देकर भविष्य की नेतृत्व टीम तैयार करने के संकेत भी दिए हैं। विभागों के आवंटन के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा राज्य प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण कमान अपने हाथों में ही रखना चाहते हैं। उन्होंने गृह विभाग, राजनीतिक विभाग, लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने पास बनाए रखे हैं। इसके अलावा वे सभी विभाग भी मुख्यमंत्री के अधीन रहेंगे, जिन्हें किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह व्यवस्था प्रशासनिक निर्णयों पर मुख्यमंत्री की सीधी पकड़ को और मजबूत बनाएगी।

असम की राजनीति में गृह विभाग को सबसे प्रभावशाली मंत्रालयों में गिना जाता है। राज्य की भौगोलिक स्थिति, सीमावर्ती क्षेत्र, सुरक्षा संबंधी चुनौतियां और विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों को देखते हुए गृह विभाग का महत्व और बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री द्वारा इस विभाग को अपने पास रखना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि वे कानून-व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी मामलों की निगरानी स्वयं करना चाहते हैं। इसी प्रकार लोक निर्माण विभाग और ऊर्जा विभाग भी राज्य के विकास एजेंडे से सीधे जुड़े हुए हैं, जिनके माध्यम से बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और निवेश योजनाओं को आगे बढ़ाया जाता है।

कैबिनेट पुनर्गठन में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा कि मुख्यमंत्री ने अपने कई वरिष्ठ सहयोगियों पर पहले की तरह भरोसा बनाए रखा। सरकार के अनुभवी चेहरों के विभागों में बड़े पैमाने पर बदलाव नहीं किया गया है। वरिष्ठ मंत्री रानोज पेगु को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी यथावत सौंपी गई है। शिक्षा क्षेत्र में चल रहे सुधार कार्यक्रमों और नई नीतियों को देखते हुए सरकार ने निरंतरता बनाए रखने को प्राथमिकता दी है। इसी प्रकार अशोक सिंघल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जिम्मेदारी फिर से दी गई है। इसके साथ ही उन्हें चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं। ऐसे में अनुभवी मंत्री के हाथों में विभाग बनाए रखना सरकार की रणनीतिक प्राथमिकता का हिस्सा माना जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, चिकित्सा संस्थानों के विकास और अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस मंत्रालय की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है।

विभागों के आवंटन में सबसे अधिक चर्चा नए चेहरों को मिली जिम्मेदारियों को लेकर हो रही है। मुख्यमंत्री ने कई ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाया है जिन्हें पार्टी और सरकार के भविष्य के नेतृत्व के रूप में देखा जा रहा है। बिमल बोरा को सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही उन्हें उद्योग, वाणिज्य और सार्वजनिक उद्यम विभाग भी दिया गया है। इतना ही नहीं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी मामलों का दायित्व भी उनके पास रहेगा। असम के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी का विशेष महत्व है क्योंकि यह राज्य को दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार, संपर्क और निवेश के नए अवसरों से जोड़ने की रणनीति का हिस्सा है। ऐसे में इस विभाग का जिम्मा मिलना बिमल बोरा के प्रति मुख्यमंत्री के विश्वास को दर्शाता है। उद्योग और वाणिज्य विभाग के माध्यम से राज्य में निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन की दिशा में भी उनसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपेक्षा की जा रही है।

हालांकि पूरे विभागीय बंटवारे में सबसे बड़ा और सबसे चर्चित निर्णय वित्त मंत्रालय को लेकर सामने आया। मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी माने जाने वाले जयंत मल्ला बरुआ को राज्य का नया वित्त मंत्री बनाया गया है। वित्त मंत्रालय किसी भी सरकार की नीतिगत दिशा तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक माना जाता है। बजट निर्माण, विकास योजनाओं के लिए संसाधनों का प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी इसी मंत्रालय के माध्यम से निभाई जाती है।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि जयंत मल्ला बरुआ को वित्त मंत्रालय सौंपना केवल विभागीय बदलाव नहीं, बल्कि सरकार के भीतर उनके बढ़ते राजनीतिक प्रभाव का भी संकेत है।

12 वर्षों की यात्रा पर प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास, विकास और कल्याण को बताया परिवर्तन का आधार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों के दौरान देश में हुए बदलावों और विकास कार्यों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने इस अवधि में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और इन परिवर्तनों के केंद्र में गरीबों, वंचितों तथा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों का कल्याण रहा है। प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर उन्होंने देशवासियों के साथ सरकार की उपलब्धियों, कल्याणकारी योजनाओं और शासन व्यवस्था में हुए सुधारों का उल्लेख किया तथा कहा कि विकसित भारत के निर्माण की दिशा में यह यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है।

सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किए गए अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2014 से लेकर वर्तमान तक की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सरकार की कार्यशैली हमेशा अंत्योदय के सिद्धांत से प्रेरित रही है। उन्होंने कहा कि शासन का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन लोगों तक विकास का लाभ पहुंचाना है जो वर्षों तक मुख्यधारा की प्रगति से दूर रहे। उनके अनुसार सरकार ने लगातार ऐसे प्रयास किए हैं जिनसे गरीब, ग्रामीण, वंचित और पिछड़े वर्गों को विकास की प्रक्रिया में समान भागीदारी मिल सके।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में देश ने सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन देखे हैं। इन परिवर्तनों का लक्ष्य केवल आंकड़ों में वृद्धि दर्ज करना नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन स्तर में सुधार लाना रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विकास तभी सार्थक माना जा सकता है जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे।

अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की कई प्रमुख योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य नागरिकों को सम्मानजनक जीवन और बेहतर अवसर प्रदान करना है। उन्होंने प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी), जनधन योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को सामाजिक परिवर्तन का आधार बताया। उनके अनुसार इन पहलों ने करोड़ों लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित किया है और उन्हें बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से वित्तीय समावेशन की दिशा में किए गए प्रयासों का उल्लेख किया। उनका कहना था कि जनधन योजना के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया, जिससे सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाना संभव हुआ। इसी प्रकार प्रत्यक्ष लाभांतरण प्रणाली ने सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और बिचौलियों की भूमिका कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता सुधारने का काम किया है। घर-घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाने और स्वच्छता को जनआंदोलन बनाने के प्रयासों से स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है, जिससे उनके जीवन में सुरक्षा और स्थिरता का भाव आया है। आयुष्मान भारत योजना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके अनुसार स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छता और वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में एक साथ किए गए प्रयासों ने समग्र विकास का आधार तैयार किया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने तकनीक और डिजिटल माध्यमों की भूमिका को भी विशेष रूप से रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी नवाचारों ने शासन प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में मदद की है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रत्यक्ष लाभांतरण प्रणाली के माध्यम से सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रही है, जिससे भ्रष्टाचार और संसाधनों की बर्बादी में कमी आई है। उन्होंने कहा कि तकनीक ने केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल नहीं बनाया, बल्कि गरीबों के जीवन को भी अधिक सुविधाजनक बनाया है।

प्रधानमंत्री के अनुसार डिजिटल परिवर्तन ने शासन और जनता के बीच की दूरी को कम किया है। विभिन्न सरकारी सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। इससे समय और संसाधनों की बचत हुई है तथा नागरिकों को अधिक पारदर्शी व्यवस्था का अनुभव मिला है। उन्होंने कहा कि नवाचार और प्रौद्योगिकी के उपयोग से प्रशासनिक कार्यक्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जब लोगों को योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिलता है तो शासन के प्रति उनका विश्वास बढ़ता है। उनके अनुसार सरकार और नागरिकों के बीच भरोसे का यह संबंध लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में लोगों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि उन्हें योजनाओं का वास्तविक लाभ सीधे प्राप्त हुआ है।

सूरत में 150 घर ध्वस्त: नगरपालिका को इसकी जानकारी नहीं है, तो फिर वह 'मिस्टर इंडिया' कौन है जिसने दिनदहाड़े यह विध्वंस किया?

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। गर्मी के मौसम में कुछ गुंडों और बदमाशों द्वारा गरीबों को बेघर करने के बाद, कतरगाम वेद्दारवाजा के पास नासिरनगर की झुग्गी बस्ती में सरजाहेर डंका के किनारे पुलिस सुरक्षा में चलाए गए विध्वंस अभियान में लगभग 150 मकान ध्वस्त कर दिए गए। अब तक कोई भी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि इन मकानों को किसने और किन नियमों के तहत ध्वस्त किया।

सूरत नगर निगम आयुक्त स्वयं इस बड़े पैमाने पर हुए विध्वंस से अनभिज्ञ कैसे हो सकते हैं, जबकि नगर निगम और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद यह मानने से इनकार किया जा रहा है कि यह विध्वंस नगर निगम ने किया है? अब जब भाजपा विधायक विनू मोर्डिया ने इस विवाद में हस्तक्षेप करते हुए स्वीकार किया है कि यह विध्वंस सूरत नगर निगम द्वारा नहीं किया गया था, तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि वह "भूत" या अदृश्य "श्री इंडिया" कौन है जिसने दिनदहाड़े एक से अधिक मशीनों की मदद से लगभग 150 लोगों के घरों को ध्वस्त कर दिया?

इस संबंध में, केंद्रीय क्षेत्र के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम की टीम वहां केवल कानूनी तौर पर "लाइन डोरी" (सड़क की सीमा और माप) करने गई थी। वहां न तो कोई आधिकारिक विध्वंस आदेश दिया गया था और न ही मिट्टी की ईंटों से बने मकानों को गिराने का कोई आदेश दिया गया था, और न ही कोई आधिकारिक कार्रवाई की गई है। नगर निगम की प्रशासनिक फाइलों में भी इस तरह के किसी विध्वंस का कोई रिकॉर्ड नहीं है।

इस स्थिति को देखते हुए विधायक ने भी गहरी हैरानी और चिंता व्यक्त की है कि अगर नगर निगम ने यह तोड़फोड़ नहीं की, तो दिनदहाड़े जेसीबी और हिताची मशीनों से पूरे झुग्गी क्षेत्र को साफ करने की हिम्मत किसने की? क्या इसके पीछे कोई भू-माफिया या बिल्डर लॉबी का हाथ है? अब इस दिशा में जांच शुरू की जाएगी।

इस प्रकार, दिन दहाड़े पूरे इलाके में अवैध तोड़फोड़ हो रही है, सैकड़ों लोग बेघर हो रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है या परोक्ष रूप से मदद कर रही है, जो सूरत पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी और गंभीर लापरवाही साबित हुई है। इस तरह एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। सूरत नगर निगम ने आधिकारिक तौर पर इस पूरे मामले से अपना हाथ खींच लिया है। जिसके कारण अब इस बात की प्रबल आशंका है कि यह पूरी कार्रवाई निजी पान-पान या भूमि हड़पने का खेल है। दूसरी ओर, तोड़फोड़ स्थल पर मौजूद भारी मशीनों के मालिक मोहसिन फ्रूटवाला ने पूरे मामले का सबसे बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि ये मशीनें सूरत नगर निगम के जाने-माने ठेकेदार तेजू राजपूत ने हमसे किराए पर ली थीं। इसलिए, यह स्पष्ट है कि यह नगर निगम से जुड़े किसी व्यक्ति का कृत्य है। फिलहाल ठेकेदार तेजू राजपूत भूमिगत है। सच्चाई तभी सामने आएगी जब वह सामने आएगा।

फोस्टा चुनाव में बढ़ी दिलचस्पी, 41 पदों के लिए 42 उम्मीदवार मैदान में

सूरत। शहर के सबसे प्रभावशाली व्यापारिक संगठनों में शामिल फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन (फोस्टा) के आगामी चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। रविवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही चुनावी माहौल औपचारिक रूप से बन गया। विभिन्न श्रेणियों से कुल 42 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए, जिससे इस बार का चुनाव व्यापारिक जगत में चर्चा का विषय बन गया है। विशेष रूप से गोल्ड श्रेणी में एक पद के लिए अतिरिक्त उम्मीदवार मैदान में उतरने से चुनावी मुकाबले की संभावना बन गई है, जबकि अन्य श्रेणियों में निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति दिखाई दे रही है।

फोस्टा के चुनाव को सूरत के वस्त्र व्यापार जगत में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह संगठन हजारों व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है और उद्योग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में संगठन की नई कार्यकारिणी और निदेशक मंडल के गठन को लेकर व्यापारिक समुदाय की विशेष नजर बनी हुई है।

रविवार, 8 जून 2026 को दोपहर 2 बजे से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हुई। चुनाव अधिकारियों की मौजूदगी में उम्मीदवारों ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने नामांकन पत्र जमा किए। पूरे दिन चली प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित माहौल में संपन्न हुई। चुनाव अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न श्रेणियों में कुल 42 नामांकन प्राप्त हुए हैं, जो संगठन के चुनाव के प्रति व्यापारियों की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है।

प्राप्त नामांकन पत्रों के अनुसार प्लेटिनम श्रेणी से 21 उम्मीदवारों ने दावेदारी प्रस्तुत की है। उल्लेखनीय बात यह है कि इस श्रेणी में निदेशक पदों की संख्या भी 21 है। इसी प्रकार डायमंड श्रेणी में 13 पदों के लिए 13 नामांकन प्राप्त हुए हैं। इन दोनों श्रेणियों में जितने पद उपलब्ध हैं, उतने ही उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। यदि जांच प्रक्रिया में सभी नामांकन वैध पाए जाते हैं और कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस नहीं लेता है तो इन दोनों श्रेणियों के सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा सकते हैं।

सबसे अधिक रोचक स्थिति गोल्ड श्रेणी में देखने को मिल रही है। यहां सात निदेशक पदों के लिए आठ उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। एक अतिरिक्त उम्मीदवार के मैदान में होने से इस श्रेणी में चुनावी मुकाबला होने की संभावना बन गई है। हालांकि अंतिम स्थिति नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। यदि कोई उम्मीदवार नाम वापस नहीं लेता है तो गोल्ड श्रेणी में मतदान की नौबत आ सकती है और व्यापारियों को अपने प्रतिनिधियों के चयन के लिए मतदान करना होगा।

नामांकन प्रक्रिया चुनाव अधिकारी अशोक जैन, बृजमोहन अग्रवाल और सचिन अग्रवाल की देखरेख में संपन्न हुई। अधिकारियों ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से संचालित किया। संगठन के सदस्यों ने भी अनुशासित तरीके से चुनावी प्रक्रिया में भाग लिया, जिससे पूरे कार्यक्रम का संचालन सुचारु रूप से हो सका।

चुनाव कार्यक्रम के अनुसार अब अगला महत्वपूर्ण चरण नामांकन पत्रों की जांच का होगा। मंगलवार, 9 जून को सभी प्राप्त नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इस दौरान उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और पात्रता संबंधी शर्तों का परीक्षण किया जाएगा। जांच पूरी होने के बाद शाम 6 बजे फोस्टा कार्यालय में वैध उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी। इस सूची के जारी होने के बाद चुनावी तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी।

नामांकन जांच के बाद उम्मीदवारों को अपने नाम वापस लेने का अवसर भी दिया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 13 जून 2026 को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक नामांकन वापसी की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इस दौरान इच्छुक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। इसके बाद अंतिम उम्मीदवार सूची जारी की जाएगी, जो चुनाव में भाग लेने वाले वास्तविक प्रत्याशियों की आधिकारिक सूची होगी।

यदि नामांकन वापसी के बाद भी किसी श्रेणी में उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध पदों से अधिक रहती है, तो वहां मतदान कराया जाएगा। चुनाव अधिकारियों ने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर 20 जून 2026, शनिवार को मतदान की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। मतदान सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रिंग रोड स्थित मिलेनियम मार्केट में संपन्न होगा। मतदान के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि सदस्य सुचारु और सुरक्षित तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

फोस्टा का चुनाव केवल संगठन की नई कार्यकारिणी चुनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सूरत के वस्त्र व्यापार की दिशा और प्राथमिकताओं को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण अवसर भी माना जाता है। संगठन के निदेशक व्यापारियों की समस्याओं, नीतिगत मुद्दों, बाजार की चुनौतियों और उद्योग के विकास से जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि चुनाव को लेकर व्यापारिक समुदाय में विशेष उत्साह और रुचि देखने को मिल रही है।

सूरत का वस्त्र उद्योग देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल केंद्रों में से एक है और फोस्टा इस उद्योग के व्यापारिक वर्ग की प्रमुख आवाज माना जाता है। ऐसे में संगठन के चुनाव का महत्व केवल उसके सदस्यों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव व्यापक व्यापारिक गतिविधियों और उद्योग से जुड़े निर्णयों पर भी पड़ता है।

फिलहाल सभी की नजरें नामांकन जांच और अंतिम उम्मीदवार सूची पर टिकी हैं। यदि गोल्ड श्रेणी में उम्मीदवारों की संख्या यथावत रहती है तो वहां चुनावी मुकाबला देखने को मिलेगा, जबकि प्लेटिनम और डायमंड श्रेणियों में निर्विरोध निर्वाचन की संभावना मजबूत दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में नामांकन वापसी की प्रक्रिया के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि फोस्टा के इस चुनाव में मतदान होगा या अधिकांश पदों पर सर्वसम्मति से प्रतिनिधियों का चयन हो जाएगा।

गुजरात में 'विकास भी, विरासत भी' का विजन हुआ साकार

डिजिटल टेक्नोलॉजी के समन्वय से संग्रहालय कलाकृतियों के संग्रह स्थान के साथ साथ संस्कृति के जीवंत केंद्र भी बने : डॉ. पंकज शर्मा, पुरातत्व और संग्रहालय निदेशक

▸▸ राज्य के संग्रहालयों में गत दो वर्षों में पहुंचे 16 लाख से अधिक आगंतुक
▸▸ गुजरात में पिछले एक दशक में बने 5 नए म्यूजियम

गांधीनगर : गुजरात में गत दो वर्षों में कुल 16 लाख से अधिक आगंतुक अलग-अलग संग्रहालयों यानी म्यूजियम को देखने के लिए पहुंचे। गुजरात सरकार के युवा सेवा और सांस्कृतिक गतिविधियां विभाग के अधीन कार्यरत पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय के निदेशक डॉ. पंकज शर्मा ने यह जानकारी दी और कहा कि बदलते समय के साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी के समन्वय से म्यूजियम अब केवल कलाकृतियों के संग्रह स्थान नहीं, बल्कि संस्कृति के जीवंत केंद्र बन गए हैं। गत 12 वर्षों में गुजरात में अनेक म्यूजियम बनाए गए हैं, जिनमें कच्छ के भूकंप का सामना करने वाले कच्छियों की जीवटता और जज्बे को दर्शाने वाला 'स्मृतिवन', गांधी विचार की विरासत को जीवंत करने वाला 'दांडी कुटीर' और प्रधानमंत्री की जन्मभूमि वडनगर की सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने वाला 'वडनगर पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय' शामिल है।

समय के अनुरूप संग्रहालयों का स्वरूप भी बदला है। आज, गुजरात के संग्रहालय केवल कलाकृति के संग्रह स्थान ही नहीं रहे, वे इंटरैक्टिव और डिजिटल लर्निंग के वैश्विक केंद्र बन गए हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्षों के दौरान, गुजरात सरकार ने देश में 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र को चरितार्थ किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के मार्गदर्शन में गुजरात ने आर्थिक विकास के साथ-साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करके नई पीढ़ी को अपनी प्राचीन विरासत से वाकिफ कराया है।

परंपरा से टेक्नोलॉजी तक, समय के साथ बदलता म्यूजियम का स्वरूप

अतीत में म्यूजियम को केवल कांच के शो-केस में रखी पुरानी मूर्तियां या सिक्के देखने का स्थान माना जाता था। लेकिन गत 12 वर्षों में गुजरात सरकार ने इस परिभाषा को बदल दिया है। आज राज्य के संग्रहालयों में एआर और वीआर (ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी), 3डी प्रोजेक्शन मैपिंग, होलोग्राम और इंटरेक्टिव टच स्क्रीन जैसी अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, ताकि युवा पीढ़ी अपनी विरासत को केवल देखे ही नहीं, बल्कि अनुभव भी कर सके।

गत 12 वर्षों में संग्रहालयों ने गुजरात की विरासत को वैश्विक पटल पर रखा

स्मृतिवन भूकंप स्मारक और म्यूजियम (भुज) : 2001 में आए विनाशकारी भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में बना यह म्यूजियम भारत का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला म्यूजियम है, जहां आगंतुक सिम्युलेटर के जरिए भूकंप का जीवंत अनुभव कर सकते हैं।

स्मृतिवन केवल म्यूजियम नहीं, एक जीवंत अनुभूति है

भुज के भुजिया डुंगर (पहाड़ी) पर बना स्मृति वन भूकंप स्मारक और म्यूजियम आज केवल गुजरात या भारत नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर आकर्षण का केंद्र बन गया है। स्मृतिवन पहुंचे आगंतुकों ने इस म्यूजियम को प्राकृतिक आपदा के खिलाफ जीवटता से दोबारा खड़े होने की गुजरात के जज्बे का प्रतीक बताया है।

म्यूजियम के अंदर बनाए गए थियेटर और डिजिटल माध्यमों के बारे में बात करते हुए पर्यटकों ने बताया कि यहां आकर 2001 के उस भयानक भूकंप का वास्तविक अनुभव होता है। भूकंप के दौरान लोगों पर क्या बीती होगी और उसके बाद कैसे पूरा गुजरात इस विभीषिका से उबरकर खड़ा हुआ दोबारा पटरी पर लौटा, इसकी प्रेरक गाथा आगंतुकों की आंखें नम कर देती है।

दांडी कुटीर : बापू के आदर्शों की अनुभूति

गांधीनगर में वर्ष 2015 में बना दांडी कुटीर म्यूजियम महात्मा गांधी के जीवन और विचारों को आधुनिक तकनीक के जरिए लोगों तक पहुंचाता है। यह 41 मीटर ऊंचा शंकु आकार का गुंबद है, जो नमक के ढेर का प्रतीक है। दांडी कुटीर वर्ष 1930 में महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए नमक सत्याग्रह का प्रतीक है।

दांडी कुटीर में प्रकाश, ध्वनि, एनिमेशन और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन की गाथा को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। दांडी कुटीर ने साबित किया है कि म्यूजियम केवल प्रदर्शन का केंद्र नहीं, बल्कि प्रेरणा का माध्यम भी बन सकता है।

वडनगर का पुरातात्विक म्यूजियम :

वर्ष 2025 में निर्मित यह म्यूजियम वडनगर के हजारों वर्ष प्राचीन इतिहास और उत्खनन के दौरान मिले पुरातात्विक अवशेषों को जीवंत रखने के लिए बनाया गया है। यह भारत में अपनी तरह का पहला म्यूजियम है, जो उत्खनन स्थल के अनुभव और उत्खनन के दौरान मिले अवशेषों को प्रदर्शित करता है।

इस अत्याधुनिक पुरातात्विक म्यूजियम में ऑगमेंटेड रियलिटी-वर्चुअल रियलिटी, 3डी डिस्प्ले, प्रतिकृति और डायोरामा जैसी इमर्सिव टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। यह स्थल आंतरिक अवलोकन के जरिए 2500 वर्षों के सात सांस्कृतिक चरणों के कालक्रमिक विकास का अद्वितीय अनुभव और समझ देता है।

लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (निर्माणाधीन) :

भारत की प्राचीन समुद्री शक्ति और सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत को उजागर करने वाले इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। लोथल में निर्माणाधीन राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम होगा। दुनिया की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के एक अहम बंदरगाह शहर के रूप में जाना जाने वाला लोथल आज एक बार फिर वैश्विक आकर्षण का केंद्र बन रहा है। लोथल समुद्री विरासत परिसर केवल एक म्यूजियम नहीं, बल्कि भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास और वैश्विक व्यापार परंपरा को दुनिया के समक्ष पेश करने वाला एक भव्य सांस्कृतिक केंद्र होगा।

जहां परंपरागत म्यूजियमों में केवल वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है, वहीं लोथल में आगंतुकों को हजारों वर्ष प्राचीन बंदरगाह शहर की जीवंत अनुभूति कराने का प्रयास किया जा रहा है। अत्याधुनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी, इमर्सिव गैलरियां, वर्चुअल प्रेजेंटेशन, समुद्री व्यापार के मॉडल और इंटरैक्टिव प्रदर्शनी के जरिए आगंतुक प्राचीन भारत के वैश्विक व्यापार और नौकायन कौशल को निकट से देख और समझ पाएंगे।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और म्यूजियम (केवड़िया) :

दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के साथ सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन और तत्कालीन भारत की रियासतों के विलय के इतिहास को दिखाने वाला यह अत्याधुनिक म्यूजियम 'विकास भी, विरासत भी' के विजन का शानदार उदाहरण है।

गुजरात सरकार आने वाले समय में भी राज्य की अस्मिता, संस्कृति और इतिहास को वैश्विक फलक पर ले जाने तथा नई पीढ़ी में अपनी भव्य विरासत के प्रति गौरव का भाव पैदा करने के लिए ऐसे ही आधुनिक प्रकल्पों का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

विश्व पर्यावरण दिवस पर बाल मंदिर व कीड्स हट स्कूल में वृक्षारोपण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा श्रीमती शालिनी वर्मा के मार्गदर्शन में बाल मंदिर व कीड्स हट स्कूल में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विशेष पर्यावरण जागरूकता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर अध्यक्षा श्रीमती शालिनी वर्मा ने विद्यार्थियों एवं उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि हमें अपनी धरती को स्वच्छ, सुंदर एवं हरित बनाए रखना है, तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा तथा लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल भी सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने सभी को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाते हुए प्रत्येक व्यक्ति से कम से कम एक पौधा लगाने और उसके संरक्षण का आह्वान किया।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण विषयक विभिन्न गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। वृक्षारोपण के माध्यम से बच्चों को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का बोध कराया गया तथा हरित वातावरण के महत्व के बारे में जानकारी दी गई।

इस अवसर पर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन की उपाध्यक्षा श्रीमती शिखा शर्मा, सचिव श्रीमती ममता सिंह सहित संगठन की अन्य सदस्याएं, विद्यालय के शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता विकसित करना तथा स्वच्छ, हरित एवं सतत् पर्यावरण के निर्माण के लिए उन्हें प्रेरित करना था।

दहेज अदाणी पोर्ट साइडिंग से लातूर के लिए पहली उर्वरक रेक लोडिंग, वडोदरा मंडल की ऐतिहासिक उपलब्धि

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल ने माल परिवहन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए दहेज अदाणी पोर्ट साइडिंग से लातूर के लिए पहली मिनी बीसीएन (BCN) उर्वरक रेक का सफल लदान किया। दहेज अदाणी पोर्ट साइडिंग अब तक मुख्य रूप से कोयला लदान केंद्र के रूप में जानी जाती रही है। ऐसे में यहां से पहली बार उर्वरक की लोडिंग होना मंडल के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके के कुशल नेतृत्व में यह कदम उपलब्ध अवसंरचना के अधिकतम उपयोग तथा नए माल यातायात को आकर्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस उपलब्धि की नींव दिसंबर 2025 में मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके के साइडिंग निरीक्षण के दौरान रखी गई थी। उन्होंने निरीक्षण के दौरान साइडिंग की क्षमता का बेहतर उपयोग करते हुए नए प्रकार के माल यातायात को आकर्षित करने पर विस्तृत चर्चा की। इसी क्रम में कोयला साइडिंग से उर्वरक लदान शुरू करने का निर्णय लिया गया, जिसने आज वास्तविक रूप ले लिया।

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 04 जून 2026 को दहेज अदाणी पोर्ट से लातूर के लिए प्रेषित इस पहली उर्वरक रेक में 21 वैगनों वाली एक मिनी बीसीएन (BCN) उर्वरक रेक का उपयोग किया गया। यह रेक लगभग 926 किलोमीटर की दूरी तय करेगी तथा इस परिवहन से मंडल रेलवे को लगभग 20.54 लाख का मालभाड़ा राजस्व प्राप्त होगा। आयातित उर्वरक की यह खेप कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं को समयबद्ध एवं सुरक्षित रूप से पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

लातूर के लिए पहली उर्वरक रेक का सफल प्रेषण न केवल वडोदरा मंडल की व्यावसायिक दूरदृष्टि और नवाचार को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिद्ध करता है कि मौजूदा रेलवे परिसंपत्तियों का उपयोग कर नए व्यापारिक अवसरों का सृजन किया जा सकता है। यह उपलब्धि दहेज अदाणी पोर्ट साइडिंग के लिए एक नई शुरुआत है और भविष्य में विभिन्न प्रकार के माल यातायात को आकर्षित करने की असीम संभावनाओं के द्वार खोलती है।

वडोदरा मंडल ग्राहकों को बेहतर माल परिवहन सेवाएं प्रदान करने, परिचालन दक्षता बढ़ाने तथा रेलवे के माल व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कच्छ के सड़क मार्गों को फोर लेन बनाने के लिए 629 करोड़ रुपए मंजूर किए

ग्रामीण क्षेत्रों को सुदृढ़ रोड कनेक्टिविटी मिलने से ईज ऑफ लिविंग तथा पर्यटन क्षेत्र का अधिक विकास होगा

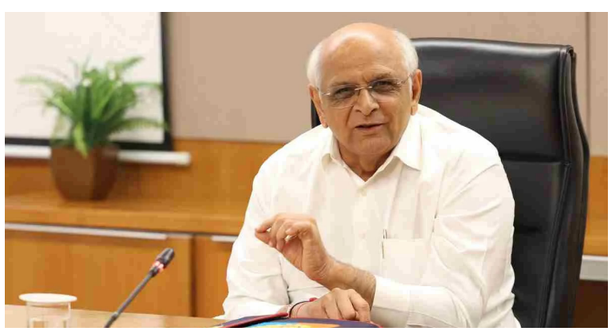

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के अति महत्वपूर्ण सड़क मार्गों को फोर लेन के रूप में विकसित करने का दृष्टिकोण अपनाया है। इस संदर्भ में; मुख्यमंत्री ने कच्छ जिले के 6 सड़क मार्गों को फोर लेन करने के लिए 629 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कच्छ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को सुदृढ़ रोड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की जन हितकारी मंशा के साथ इन सड़क मार्गों को चार मार्गीय करने के लिए वित्तीय आवंटन किया है। इसमें मुंद्रा-लुणी-वडाला रोड के 4.1 किलोमीटर, वाइडनिंग तथा इम्प्रूवमेंट ऑफ देशलपर सिरचा रोड 5.1 किलोमीटर, मुंद्रा-झरपरा-कांडगरा-ध्रब तथा झरपरा गाँव के बाईपास रोड के 5.5 किलोमीटर, नावीनल गाँव के बाईपास रोड के 3.3 किलोमीटर, मोटा कांडगरा गाँव के 4.5 किलोमीटर और मुंद्रा-झरपरा-कांडगरा रोड चेनेज 19 से 39 के 20 के किलोमीटर का समावेश होता है। फोर लेन बनने के परिणामस्वरूप ये सड़क मार्ग ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण एवं सुविधायुक्त बनेंगे। इतना ही नहीं; बाईपास बनने से मुंद्रा बंदरगाह तथा आसपास के छोटे-बड़े औद्योगिक-वाणिज्यक क्षेत्रों में आवागमन करने वाले भारी वाहन तेजी से और सुरक्षित माल परिवहन कर सकेंगे। इन सड़क मार्गों का विकास होने से कच्छ में पर्यटन क्षेत्र को भी अधिक बल मिलेगा और लोगों का ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा।

विश्व पर्यावरण दिवस पर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन की हरित पहल, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु औषधीय पौधों का वितरण

पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन (WRWWO) द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस की भावना को साकार करते हुए 8 जून, 2026 को अंधेरी रेलवे कॉलोनी में जागरूकता एवं वृक्षारोपण संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व संगठन की अध्यक्षा श्रीमती सुजाता पाण्डेय ने कार्यकारिणी समिति की सदस्याओं के साथ किया।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, श्रीमती सुजाता पाण्डेय एवं कार्यकारिणी समिति की सदस्याओं द्वारा नीम, सहजन (मोरिंगा) तथा आंवला जैसे औषधीय पौधों से युक्त एक 'आरोग्य वाटिका' की स्थापना की गई। इस पहल का उद्देश्य दैनिक जीवन में औषधीय पौधों के महत्व को रेखांकित करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता को बढ़ावा देना है।

इस अवसर पर श्रीमती पाण्डेय ने रेल कर्मचारियों, उनके परिजनों तथा सामाजिक कल्याण केंद्र में उपस्थित बच्चों से संवाद किया। केंद्र की सदस्याओं ने वर्षभर संचालित विभिन्न कल्याणकारी एवं सामुदायिक विकास गतिविधियों, जैसे राष्ट्रीय पर्वों के आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों आदि की जानकारी प्रस्तुत की।

श्रीमती पाण्डेय ने रेलवे कॉलोनी में स्वच्छ एवं हरित वातावरण बनाए रखने के लिए वहां के निवासियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में सामूहिक सहभागिता तथा पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी समुदायों के निर्माण के महत्व पर बल दिया। घरेलू बागवानी को प्रोत्साहित करने तथा औषधीय पौधों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कॉलोनीवासियों को नींबू, लेमनग्रास, कड़ी पत्ता एवं पान के पौधों सहित विभिन्न पौधे एवं गमले वितरित किए गए। इस पहल का उद्देश्य परिवारों को अपने घरों में उपयोगी पौधे उगाने तथा पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। यह कार्यक्रम घर-घर में औषधीय पौधे लगाने के पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य संबंधी लाभों के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने का एक सार्थक माध्यम सिद्ध हुआ।

912 करोड़ रुपये के कथित बैंकिंग घोटाले ने खड़े किए गंभीर सवाल, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

नई दिल्ली। देश के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े एक कथित 912 करोड़ रुपये के घोटाले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है। इस मामले में दायर जनहित याचिका ने न केवल बैंकिंग प्रणाली की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न खड़े किए हैं, बल्कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी कॉरपोरेट संस्थाओं के बीच होने वाले वित्तीय लेनदेन की निगरानी व्यवस्था पर भी नई बहस छेड़ दी है। याचिकाकर्ताओं ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा नोएडा स्थित एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से जुड़े वित्तीय लेनदेन में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। याचिका के अनुसार इन लेनदेन के माध्यम से बड़े पैमाने पर बैंकिंग और कॉरपोरेट धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया हो सकता है, जिसकी निष्पक्ष जांच देश के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मामला केवल किसी एक कंपनी या संस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे बैंकिंग तंत्र की विश्वसनीयता से जुड़ा विषय है। यदि आरोपों में सच्चाई पाई जाती है तो इसका प्रभाव न केवल संबंधित बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर पड़ेगा, बल्कि निवेशकों और आम खाताधारकों के विश्वास पर भी असर पड़ सकता है। इसी कारण उन्होंने न्यायालय से इस मामले को सामान्य जांच के बजाय विशेष निगरानी में जांच कराने की मांग की है। याचिका में केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह एक उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग अथवा विशेषज्ञ समिति का गठन करे। प्रस्तावित समिति में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करने का सुझाव दिया गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि मामला बहुआयामी है और इसकी जांच के लिए विभिन्न नियामक एवं जांच एजेंसियों की विशेषज्ञता आवश्यक होगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष

विकसित भारत का अमृतकाल : 'विकसित भारत@2047' के संकल्प के साथ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ता देश

गांधीनगर : 26 मई, 2014 को श्री नरेन्द्र मोदी ने पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को देश की जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिला और वर्ष 2024 में उन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। 26 मई, 2026 को प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं।

गत 12 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दिशादर्शन में भारत ने विकास, सुशासन, गरीब कल्याण और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए अध्याय लिखे हैं। प्रधानमंत्री के दृढ़ नेतृत्व तथा दूरदर्शी विचारधारा से भारत ने एक नई दिशा प्राप्त की है। उन्होंने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र को प्राथमिकता दी है और वे 'विकसित भारत@2047' के संकल्प के साथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उनके इन 12 वर्षों के कार्यकाल के दौरान देश ने इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, उत्पादन, खेलकूद तथा सामाजिक सुधार जैसे अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात राज्य देश की इस विकास यात्रा में अग्रसर रहकर 'विकसित गुजरात से विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। गुजरात आज केवल औद्योगिक राज्य के रूप में ही नहीं; बल्कि नवाचार, हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर उत्पादन, वैश्विक निवेश एवं आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का केन्द्र बनकर में उभरा है। गत 12 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के केन्द्रीय नेतृत्व अंतर्गत गुजरात ने विकास, नवाचार एवं प्रगति का एक अनूठा मॉडल स्थापित किया है, जो आज समग्र देश के लिए प्रेरणारूपी बना है।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गुजरात द्वारा प्राप्त की गई बड़ी भेंट

प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के मात्र 17 दिनों में श्री नरेन्द्र मोदी ने सरदार सरोवर बांध पर दरवाजे लगाने की मंजूरी देकर गुजरात के करोड़ों लोगों का वर्षों पुराना सपना साकार किया। आज सरदार सरोवर बांध अपने पूर्ण जल स्तर तक पहुँचकर छलक रहा है। भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, गांधीनगर तथा दाहोद का अभूतपूर्व विकास हुआ है।

गुजरात के अहमदाबाद शहर तथा महाराष्ट्र के मुंबई शहर को तीव्र गति से कनेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात की जनता को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की भेंट दी है। इसके अतिरिक्त; जामनगर में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसीन, राजकोट में हीरासर स्थित प्रथम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, अत्याधुनिक सुविधाओं वाला राजकोट एम्स अस्पताल, नवसारी में पीएम मित्र पार्क, भरूच में बल्क ड्रग पार्क, कच्छ के खावडा में विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, दाहोद में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन उत्पादन इकाई, वडोदरा में टाटा फैसिलिटी सी-295 एयरक्राफ्ट का उत्पादन करने के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स, भावनगर में विश्व का प्रथम सीएनजी टर्मिनल पोर्ट, द्वारका तथा बेट द्वारका को जोड़ने वाला अत्याधुनिक सिग्नेचर ब्रिज सुदर्शन सेतु, साणंद में माइक्रोन सेमीकंडक्टर फैसिलिटी और 'केन्स सेमीकॉन' ओएसएटी प्लांट का शुभारंभ आदि जैसी परियोजनाओं की गुजरात को भेंट मिली है। गुजरात आज भारत के सेमीकंडक्टर हब के रूप में उभर रहा है।

उनके सुदृढ़ नेतृत्व में गुजरात में रेलवे कनेक्टिविटी भी मजबूत बनी है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के अतिरिक्त; प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पर्यटक आसानी से पहुँच सकें; इसके लिए केवडिया तक रेलवे कनेक्टिविटी प्रदान की है। आज भारतीय रेलवे की 8 ट्रेनें केवडिया तक के रूट पर चल रही हैं। सितंबर, 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात को प्रथम वंदे भारत ट्रेन की भेंट दी थी। हाल में गुजरात में पाँच वंदे भारत सेमी हाईस्पीड ट्रेनें चल रही हैं। इसके अलावा; भुज तथा अहमदाबाद के बीच नमो भारत रैपिड रेल की भेंट भी गुजरात को मिली है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में अहमदाबाद मेट्रो और सूरत मेट्रो परियोजना की भेंट दी है। आज अहमदाबाद तथा गांधीनगर में सफलतापूर्वक मेट्रो रेल चल रही है, जो नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा प्रदान कर रही है। गुजरात आज केवल देश के औद्योगिक राज्य के रूप में ही नहीं; बल्कि नवाचार, हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर उत्पादन, वैश्विक निवेश तथा आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के केन्द्र के रूप में उभरा है। गुजरात ग्रीन एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस तथा टेक्नोलॉजी क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है। गत 12 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के केन्द्रीय नेतृत्व में गुजरात ने विकास, नवाचार और प्रगति का एक अनूठा मॉडल स्थापित किया है।

गुजरात में 'विकास भी, विरासत भी' का मंत्र हो रहा है चरितार्थ

सोमनाथ मंदिर पर हुए प्रथम आक्रमण के 1000 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर नरेन्द्रभाई ने जनवरी 2026 में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया था। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के माध्यम से केवल मंदिर के इतिहास का स्मरण ही नहीं किया गया; अपितु राष्ट्र के स्वाभिमान, संघर्ष एवं पुनरुत्थान की भावना को नई पीढ़ी तक पहुँचाने का प्रयास हुआ है।

वडनगर में निर्मित भारत का प्रथम आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियेंशियल म्यूजियम भारत की प्राचीन नगर संस्कृति, ज्ञान परंपरा तथा ऐतिहासिक वैभव को आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से विश्व के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है, जबकि लोथल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने वाला एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है। इस प्रकार; एक ओर गुजरात में सेमीकंडक्टर, बुलेट ट्रेन, गिफ्ट सिटी, धोलेरा-एसआईआर जैसे प्रोजेक्ट आकार ले रहे हैं, तो दूसरी ओर राज्य की विरासत एवं इतिहास को भी गुजरात गर्वपूर्वक विश्व के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल के ये 12 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रहे हैं। यह समयावधि केवल उनके कार्यकाल के रूप में ही नहीं; बल्कि भारत के आत्मविश्वास, सुशासन, विकास एवं वैश्विक प्रतिष्ठा के नए अध्याय के रूप में पहचानी जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भारत को पुनः 'विश्व गुरु' बनाने के लक्ष्य के साथ निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में 'विकसित भारत@2047' के रोडमैप के साथ वर्ष 2047 में स्वतंत्रता की शताब्दी तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भारत अवश्य पूर्ण करेगा।